15.32 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Seventy Second Report

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : I beg to move :

"That this House do agree with the Seventy-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 28th March, 1984."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That this House do agree with the Seventy-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 28th March, 1984."

The motion was adopted.

15.33 hrs.

RESOLUTION RE : UNEMPLOYMENT—*contd.*

MR. DEPUTY SPEAKER : The House now shall take up further discussion on the following resolution moved by Shri T.S. Negi on 16 December, 1983 :—

"This House expresses its concern over the growing unemployment in the country and urges upon Government to take immediate steps to raise a land army of unemployed persons to take up—

(a) the work of deepening the river bads of major rivers ;

(b) the afforestation programme throughout the country including Himalayan region in such a way as to cover at least one-third part of the land ;

(c) extensive land conservation programme ;

(d) linking of major rivers of the country ;

and recommends that Government should pay an unemployment allowance of at least Rs. 100 per month to all unemployed persons."

Shri Jatiya was on his legs. He is not present in the House now. His speech would be treated as concluded. We have already taken 4 hours and I think we can conclude it today. Some more members are here. Shri Girdhari Lal Vyas.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, श्री नेगी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं, मगर एक बात मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एम्पलायमेंट की समस्या ऐसी है जिसे हल किये बिना हमारा देश ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता, इसलिये इसे फंडामैंटल राइट में इन्क्लूड किया जाना चाहिये। अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है, जिससे लोगों को रोजगार और धन्धा मिल सके, हालांकि सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चालू किये है जिससे लाखों-करोड़ों को कामकाज मिल सके, लेकिन फिर भी जिस प्रकार की गारन्टी सरकार की तरह से होनी चाहिये, वह अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आप गारन्टी की बात करते हैं, आप आबादी बढ़ाते जाइये और गवर्नमेंट को बोलिये कि नौकरी दे, यह ठीक नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह आपके हाथ में नहीं है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चे के लिये तरसते हैं, जिनके बच्चा नहीं होता है। अलग-अलग तरह की बातें हैं। इस बारे में आप अपने घर से कोशिश कीजिये, चैरिटी बिगिन्स एट होम।

मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें कोई भी आदमी बगैर कामकाज के न रहे।

मैं इस बात से इत्तिफाक नहीं करता जैसा कि कुछ लोग करते हैं कि 100 रुपये अन-एम्पलामेंट का भत्ता दिया जाये। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें कोई भी आदमी बेरोजगार न रहे। इसे आप कैसे लागू करेंगे, यह आपके देखने का काम है।

एन० आर० ई० पी० का प्रोग्राम आपने लागू किया जिसमें लाखों लोगों को धन्धा देने की बात है, लेकिन क्या यह प्रोग्राम ठीक प्रकार से लागू हो रहा है? बहुत सी स्टेट्स के पास एन० आर० ई० पी० के लिए फंड अवेलेबल नहीं है। इसलिये लाखों लोग जिनको भारत सरकार रोजगार देना चाहती है, इंदिरा जी का जो 20-सूत्री कार्यक्रम है, उसको स्टेट गवर्नमेंट्स इम्पलीमेंट नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनके पास फंड्ज नहीं हैं। इसलिये इस कार्यक्रम को या तो भारत सरकार खुद चलाये या फिर ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे राज्य सरकार अगर अपना कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं देती, जिसके कारण प्रोग्राम फेल हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये जिससे ये प्रोग्राम व्यवस्थित तरीके से ठीक बैठ सके।

हमारे बहुत से भाइयों ने फूड फार वर्क कार्यक्रम की बात कही है। इस कार्यक्रम को जनता पार्टी के समय में चलाया गया था। हमारे वेस्ट बंगाल के भाई इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन हमने यह देखा है कि इस प्रोग्राम में बहुत से लोगों ने अपने घर बनाने के सिवाय और कोई काम नहीं किया है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : कहां किया है?

श्री गिरधारी लाल व्यास : कई जगह ऐसा हुआ है कि इस कार्यक्रम में जितना गेहूं लोगों को देने के लिये दिया गया, वह बांटने वालों द्वारा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बांट दिया गया या उसका उपयोग वहां के सरपंच ने और ऐसे प्रतिनिधियों ने गलत तरीके से किया जिसकी वजह से जिनको काम के बदले अनाज मिलना चाहिये था, वह नहीं मिल सका।

जनता पार्टी की सरकार की बदनामी इसी वजह से हुई कि गांव-गांव में जो सरपंच बैठे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया जिसके कारण हिन्दुस्तान की जनता ने उनको पहचान लिया कि जनता पार्टी के लोग करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। आज जो लोग करप्शन की बात यहां करते हैं, इस करप्शन की सबसे बड़ी देन जनता पार्टी की तरफ से हुई है। इन लोगों ने लोगों को भ्रष्ट करने

[श्री गिरधारी लाल व्यास]
के सिवाय और किसी प्रकार का कोई कार्य-क्रम नहीं चलाया।

एन० आर० ई० पी० में ऐसी खराब व्यवस्था आज भी हो रही है जिसको देखना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि सरपंच या दूसरे ऐसे लोगों को जो काम करने के लिये देते हैं, वह ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट हो रहा है या नहीं। यह देखना नितान्त आवश्यक है कि एन० आर० ई० पी० की हालत वह न हो जाए, जो जनता पार्टी के शासन-काल में फूड फार वर्क कार्यक्रम की थी। अगर इस कार्यक्रम को ठीक प्रकार से चलाया जाए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा विकास होगा। लेबर मिनिस्टर को यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि क्या एन० आर० ई० पी० के लिए स्टेट्स के कान्ट्रीब्यूटरी फंड्ज ऐवेलेबल हैं या नहीं और क्या इस योजना के अन्तर्गत लोगों को काम मिल रहा है।

भारत सरकार ने आई०आर०डी०पी० का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया है, जिसके अन्तर्गत हर एक ब्लाक में 600 फैमिलीज को और देश भर में एक करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाएगा। मगर क्या श्रम मंत्री ने जा कर देखा है कि क्या आई० आर० डी० पी० का काम ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट हो रहा है? मैं समझता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट इस बारे में बिल्कुल निष्क्रिय है और उसने किसी भी ब्लाक में इस कार्यक्रम की क्रियान्विति को देखने की कोशिश नहीं की है।

इस योजना के अधीन जो सबसिडी का पैसा दिया जाता है, उस पर विकास अधिकारी, बैंकों के अधिकारी और जानवरों के डाक्टर गिद्ध की तरह निगाह रखते हैं और उसका आधे से ज्यादा पैसा वे खा जाते हैं। यह सुझाव दिया गया है कि सबसिडी की व्यवस्था को समाप्त कर के लोगों को बिना ब्याज के ऋण दिया जाए, जिससे उनको पूरा पैसा मिल सके और वे मेहनत करके अपने स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर सकें। क्या श्रम मंत्रालय भारत सरकार को यह सुझाव देगा, जिससे बैंकों के जरिये से की जा रही इस लूट-पाट को बन्द किया जा सके।

हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या ट्राइसम की योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से काम करने वाले कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए सब सुविधाएं दी गई हैं। क्या उनको बैंकों के ऋण मिल रहे हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग की ठीक व्यवस्था है और क्या उनको नियमित रूप से स्कालरशिप दिए जा रहे हैं, श्रम विभाग को इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इन योजनाओं को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करना चाहिए।

यह काम बहुत बड़ा है और इसके लिए बहुत बड़ी मशीनरी की जरूरत है। मैं समझता हूं कि वर्तमान मशीनरी इस काम को ठीक प्रकार से नहीं कर सकेगी। तो क्या आप कोई ऐसी नयी व्यवस्था बनाएंगे कि जिस से ये जो कार्यक्रम हैं जो हमारी प्रधान मंत्री जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के जरिए दिए हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों को एम्पलायमेंट मिलने की व्यवस्था है वह ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट किए जा सकें। उसके लिए कोई ऐसी नयी मशीनरी इन्वाल्व करेंगे जो इसकी देख रेख रखे कि यह ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट हो रहे हैं या नहीं।

इन सारे कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट करने के लिए आपने और क्या-क्या किया है ? बहुत सी जगह जैसे काटेज इंडस्ट्रीज हैं, इनके जरिए से लाखों लोगों को इस देश के अन्दर एम्पलायमेंट मिला है। खादी ग्रामोद्योग के जरिए 70-80 लाख लोगो को एम्पलायमेंट मिलता है। इन चीजों को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है जिससे कि हम बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देकर उनकी गरीबी दूर कर सकें और एम्पलायमेंट की प्राबलम को हल कर सकें ।

अभी थोड़े दिन पहले एक बिल यहां पर लाया गया था। उस पर बोलते हुए मैंने उस दिन भी कहा था कि बड़े-बड़े लोग काटेज इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे है। जो बड़े-बड़े मोनोपली हाउसेज हैं वह इसमें प्रवेश कर रहे हैं। इनकी वजह से जो छोटे उद्योग हैं जो छोटे लोगों द्वारा चलाए जाने चाहिए उसमें ये बड़े-बड़े लोग घुस कर इस जूरिस्डिक्शन में नाजायज हस्तक्षेप कर रहे हैं।

15.47 hrs.

[SHRI R.S. SPARROW *in the Chair*]

ये मोनोपली हाउसेज उसके जरिए से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे छपाई का काम है जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के जरिए से होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बड़े-बड़े लोग जो कम्पोजिट मिल वाले हैं, जैसे भिवानी में बिरला की मिल है, उसने टेक्सटाइल का सारा काम समाप्त कर दिया और दो ढाई हजार मजदूरों को बेकार कर दिया, पैसा कमाने के लिए दूसरी जगह से कपड़ा ला कर अब वह वहां उसमें छपाई का काम करते हैं जो कि स्माल स्केल इंडस्ट्री से होना चाहिए। तो इस तरह से ये बड़े-बड़े लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिस से गरीब लोगों को एम्पलायमेंट न मिल सके और अपनी मशीनों के जरिए से उन्होंने छपाई करना शुरू कर दिया है। इस तरह से इस सारी व्यवस्था को वह बिगाड़ रहे हैं। तो ये जो मोनोपली हाउसेज स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं उनको रोकने की आवश्यकता है, तभी जा कर गरीब लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा उपलब्ध हो सकता है और उनको कामकाज उपलब्ध हो सकता है।

आप के तहत एम्पलायमेंट एक्सचेंज के दफ्तर हैं। उनके अन्दर ऐसी व्यवस्था है कि जो पैसा दे दे उसको तो नौकरी का कार्ड भी मिल जायगा और रोजगार भी मिल जायगा लेकिन जो दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह और 20-20 साल से उसमें रजिस्टर्ड हैं उनका वहां पर एम्पलायमेंट का कार्ड ही नहीं मिलता और हमारे जैसा आदमी कोई कभी कह दे कि पांच सात साल से इनका रजिस्ट्रेशन आपके यहां है, इसके बाद भी कार्ड क्यों नहीं मिलता तो वह कहते हैं कि आप हमारे काम में नाजायज हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस प्रकार के अधिकारी आपने वहां बैठा रखे हैं। अधिकारी तो वहां ऐसे होने चाहिए जो लोगों के घरों में जा कर पूछें कि तुम को काम धन्धा मिला या नहीं। लेकिन ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को आपने बैठा रखा है कि जो उनकी ओर आंखें निकाले और पब्लिक के चुने हुए लोगों के साथ गुर्राए। ऐसे लोग एम्पलायमेंट एक्सचेंज में रहेंगे तो निश्चित तरीके से आपकी पालिसीज को वह कभी भी इम्पलीमेंट नहीं कर पाएंगे।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]
इसलिए इस व्यवस्था को भी बदलने की जरूरत है।

खादी और ग्रामोद्योग बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को एम्पलामेंट दे सकता है लेकिन क्या वह ठीक प्रकार से चल रहा है ? आज खादी ग्रामोद्योग की बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो फार्स हैं और करोड़ों रुपये इन संस्थाओं के इन्होंने समाप्त कर दिए। इस चीज को और आगे बढ़ाने की जरूरत है लेकिन यह आपको देखना चाहिए कि कौन-कौन सी संस्थाएं ऐसी हैं जो सरकारी धन ले कर उसका दुरुपयोग कर गई। उसके जरिए से जो एम्पलायमेंट जुलाहों, बुनकरों और कतिनों को मिल सकता है वह मिला है या नहीं ? इसका कपड़ा बुनने के लिए लोगों को दिया जाना चाहिए, वह उनको मिला है या नहीं ? अगर नहीं मिला है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? अगर आप हर क्षेत्र में माकूल व्यवस्था करेंगे तभी जो हमारे कार्यक्रम हैं उनको कार्यान्वित करने में सफल हो सकेंगे। आज जितने भी लोग अनएम्पलायड हैं, चाहे वे रूरल एरियाज के हों या अरबन एरियाज के हों, उनको रोजगार देने के लिए आप पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्या विशेष व्यवस्था करने जा रहे हैं ? जब तक आप उचित प्रकार से पूरी व्यवस्था नहीं करेंगे, यह अनएम्पलायमेंट की जो प्राब्लम है वह साल्व नहीं हो पायेगी। नेगी जी ने जो यहां पर कहा है उससे तो मैं इत्तफाक नहीं रखता कि एम्पलायमेंट भत्ता दिया जाए बल्कि मैं तो इस विचार का हूं कि सभी को काम मिलना चाहिए। और सभी को काम देने के लिए आपको उसके लिए उचित व्यवस्था करनी होगी। जैसे आज जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है, उसको आप समाप्त कर दीजिए—वह चाहे पी० डब्लू० डी० में हो, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट में हो, फारेस्ट डिपार्टमेंट में हो, कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट में हो—जहां भी ठेकेदारों को काम दिया जाता है, उस प्रथा को आप समाप्त कीजिए। आज ठेकेदार जिस प्रकार से शोषण करते हैं उसको देखते हुए इस प्रथा को समाप्त करना नितान्त आवश्यक है। इन सारे कार्यों को आप डिपार्टमेंट के तहत करवाइये ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।

मैं श्रम मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से सारे कार्यक्रमों को इंप्लीमेंट करने के लिए आप एक समुचित मशीनरी इवाल्व करें और उसके जरिए से अनएम्पलायमेंट की प्राब्लम को साल्व करने की व्यवस्था करें।

MR. CHAIRMAN : The time allotted for this Resolution is over. If the House so desires, we can extend the time by one hour. Is it the pleasure of the House that it should be extended by one hour ?

SOME HON. MEMBERS : Yes.

MR. CHAIRMAN : All right, it is extended by one hour. Since a number of hon. Members have expressed their desire to participate in the discussion, I would request the hon. Members to be brief.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Sir, unemployment is growing in this country very fast and the Government has almost lost its control over this problem. At the time this Government took charge, the number of unemployed was less than one crore, according to the registers maintained with the employment exchanges. Now it has gone up to 2.5 crores. This indicates

the functioning of the Government that works. This clearly proves that this Government has completely failed in eradicating unemployment.

In the Budget, which was placed before the Parliament recently, there was no direction; no indication of drastic measures to be taken in order to eradicate this unemployment. I also find that so far as the backward areas are concerned, the Government did not lay emphasis on development of those areas in order to eradicate unemployment. That shows that the Government has no intention to face this challenge of unemployment which is today before this nation.

Everywhere we are finding crisis in one form or another is prevailing. Today about 70 per cent of the people of this country are below the poverty line. The Government says that their number is about forty or fifty per cent, but the reality is that still seventy per cent of the people are not getting those facilities and amenities which are essential and fundamental in nature.

We have come to know that the Government has decided to change the definition of the poverty line so that the people, who are below the poverty-line, may be told that they are not below the poverty-line, and their poverty has been removed. This kind of process is extremely wrong. Therefore, I would urge upon the Government not to try to change the definition instead of trying to create a situation where their economic condition is improved.

Sir, it is the most surprising thing and one must express regret over the priorities which have been fixed by this Government. In various parts of the country still we are observing that starvation deaths are taking place; drinking water is not available in many villages; diseases like malaria, Kalazar, small-pox etc. are increasing and the people are dying because of them. All such types of things are there and the Government is not going to solve these problems. The priorities which have been fixed are something different. Priorities are on the construction of five-star hotels, production of television sets, organising of ASIAD and the international conferences. I just mentioned all these things to indicate that the Government is not very serious in eradicating unemployment and other problems which are really concerning the people today. Government's priorities are different.

This bank loan facilities are also being misused. The Government has said that it is being done in order to eradicate unemployment, but we are findiniug that there are lots of bunglings taking place. Lot of corruption is there and bribery is taking place before a loan is given to the needy. In my district, I can say, there are people who are taking money from those appllicants and only then loan is being given to them. I have already written a letter to the Prime Minister in this matter, but I don't know whether any action is being taken to stop these mal-practices. Previously whenever a loan was given to any person, a project report or a scheme was presented to the Bank. Now, this process is being dispensed with and only money is being distributed. Even if they are distributing money, they should give a project or scheme to that particular person so that he can work on that particular scheme. But the Government is not doing that also. That indicates that whatever the Government is doing today in the name of eradicating unemployment, is nothing but a populist slogan to get votes in the coming elections. But, Sir, I may warn this will ultimately ruin the national economy and the same time may not solve the problem of unemployment as well.

I would request the Hon. Minister to see that the land reforms are carried out properly. Unless these land reforms are carried out properly, unemployment cannot be eradicated from this country.

The Government must also lay stress on the animal husbandry programme so

[Shri Harish Bahadur]

that unemployment to a certain extent is eradicated by involving some people in this particular field.

As the Hon. Member, Shri T.S. Negi has said in his Resolution, programmes like deepening of river beds, afforestation, land conservation programme and linking of rivers etc. must be taken up. If these things are done, certainly many people of this country who are unemployed today, will be absorbed and unemployment can be eliminated to a large extent.

Sir, the Hon. Minister must take care of all these points and suggestions which I am putting before him.

Sir, there was one Garland Canal Scheme. According to that scheme, many rivers of this country would have been connected through the canals and many people would have been given employment. And many people would have been given employment in that process. But I do not know whether the Government is taking such type of measures or not, whether they are studying that particular thing or not I would like to appeal to the Government, through you, Sir, that they must try to resolve this crisis by taking up such programmes by which we can provide employment to millions of people.

So far as this unemployment allowance is concerned, we know that the West Bengal Government is providing this allowance But the Central Government could not do it. Some of the State Governments are already providing it In Kerala also the previous Government was providing it. It was not started by the present government, which is a Congress (I) Government. Therefore the Government must give serious thought to it. I do not say that they should just start providing it immediately, but they must consider it sympathetically, and if they can do anything in this regard, they should do it

So far as the NREP scheme is concerned so many things have already been said here. I would like to say that there is a lot of corruption and people are not working properly today. We are approving and giving several programmes, but generally we are finding that there is complacency on the part of the persons concerned who are handling these programmes and they are not taking much interest. Therefore, the State Governments must be given clear-cut directions by the Central Government and try to streamline the whole thing so that this NREP scheme will be a perennial scheme in which many people may be given employment.

So far as the development of backward areas is concerned, I would say that the Government is still not taking interest in this regard. There are various parts of this country which have been declared backward areas in many States like Orissa, Bihar, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and other States. So far as the north-eastern region is concerned, that is completely a backward area, as also the U P. hills, but the Government is not taking much interest in developing those areas. I would suggest that there must be provision for the development of those areas and drastic measures must be taken for this purpose.

So far as our area, eastern U.P is concerned, I would like to suggest that we have already had discussions a number of times about the setting up of bagasse based paper industry in that area. There is plenty of bagasse there Therefore, they should set up the bagasse based paper industry there. Something should be done in this regard Whenever we have placed this matter before the Government, we have been given a reply that it is a difficult task because in several other regions bagasse is not plenty and all that But we feel that certainly, at least one bagasse based paper industry can easily be run in that area and by doing so, we will be able to eradicate unemployment to a large extent.

There was a propoal for setting up a railway coach factory in Gorakhpur. But the Hon. Minister of State for Labour is trying to see that that location is not finalised and he wants that it should be brought to Allahabad because he comes from Allahabad and he wants to politicalise the whole thing. And there are several people who are trying to shift the location from Gorakhpur to Allahabad. So, I would like to know from the Government, through you, and specially the Minister of State for Labour...........

Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR) : I would like to clarify the position here. I would like to inform Mr Harikesh Bahadur that there is no question of any decision being taken here for the installation of that railway coach factory. But the railway coach factory was previously decided to be set up at Allahabad and it was the original proposal. But it is you who are telling that it is going to be shifted from Gorakhpur to Allahabad. Actually the proposal is to set it up at Allahabad. There is no question of my interest here.

SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR (Trivandrum) : Whether it is set up in Allahabad or in Gorakhpur, we accept.

SHRI HARIKESH BAHADUR : Does it mean that the railway coach factory is going to be set up in Allahabad, as the Minister is telling that there is a proposal earlier for that particular purpose ? But whenever we had raised this issue, we had always been given to understand that the location has not still been finalised. We have been knowing that it would be Gorakhpur. The ministers in the Union Government from Allahabad are trying that this should be established at Allahabad. It is because of political reasons or because of the coming election.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Why not shift the ministers from Allahabad to Gorakhpur ?

SHRI HARIKESH BAHADUR : I would request the Prime Minister to shift them to Gorakhpur from Allahabad.

Suppose we establish this factory in Gorakhpur, we will be able to eradicate unemployment to a very large extent in Eastern U P. and Western Bihar. Therefore, it is a problem of five crores of people. That is why we have been consistently and constantly demanding that this factory should be set up in Gorakhpur. It is hoped that the Hon. Minister will definitely try to persuade the Railway Minister as well as the Planning Minister to set up that factory in Gorakhpur.

My last point is about the casual labour in Railways. There are several workers who work in Railways on daily wages. After two, three years they are removed from there. That adds also to unemployment. I would request the Hon. Labour Minister to see that these people are absorbed and not retrenched. Otherwise, unemployment will increase. He may kindly request the Railway Minister to solve the problem of casual labour in Railways as much as possible.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, आज इस सदन में बेरोजगारी की समस्या पर जो चर्चा हो रही है, वह हमारे देश में एक ज्वलंत प्रश्न है। हकीकत यह है कि आजादी के बाद हमारे देश की आबादी बहुत बढ़ी है और उस के साथ-साथ बेरोजगारी भी बहुत बढ़ती चली गई।

अभी 6 मार्च को माननीय श्रम मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में लोक सभा को बताया था कि इस वक्त हमारे देश में करीब 2 करोड़ 19 लाख लोगों के नाम रोजगार दफतरों के रजिस्ट्रों में लिखे हुए हैं और इस

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

में से करीब 1 करोड़ 9 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं और आई० टी० आई० से भी शिक्षा पाए हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वह संख्या है, जोकि आसानी से एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज में जा कर अपना नाम लिखा देती हैं आप कल्पना कीजिए कि ऐसे इलाके भी हैं, जहां पर एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज नहीं है और देश के लड़के या लड़कियां रोजगार के दफतरों में जाकर अपना नाम नहीं लिखा सके, तो उन की संख्या कितनी होगी। मेरा अपना अनुमान है कि आज इस देश में ऐसे कई करोड़ की तादाद में नौजवान युवक और युवतियां हैं, जो काम की तलाश में मारे-मारे फिर रहे हैं और उन को रोजगार नहीं मिल पा रहा है हालांकि हमारी सरकार बड़ी सचेत है और इस देश के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए काफी प्रयत्नशील है और उस ने अनेक प्रकार की योजनाएं भी बनाई हैं और कुछ विचाराधीन भी हैं।

सब से पहले तो आप प्रधान मंत्री जी के बीस सूत्री कार्यक्रम को ही ले लीजिए। इस से देश के गरीब, मजदूर, शोषित सर्वहारा और मध्यम वर्ग के लोगों को ही फायदा होने वाला है और यह उन्हीं के लिए है। क्या आप यह समझते हैं कि यह बीस सूत्री कार्यक्रम टाटा, बिड़ला और दूसरे बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है और क्या इस से उन को लाभ होने वाला है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, वे भ्रम में हैं। ऐसी बात नहीं है। यह तो देश के किसानों, मजदूरों और कमजोर वर्गों के लिए है और उन को इस से लाभ पहुंचने वाला है। यह बात दूसरी है कि इस के इम्लीमेंटेशन में नौकरशाही आड़े आ रही है और इस का जितना लाभ गरीबों और मजदूरों को मिलना चाहिए, उतना उन को नहीं पा रहा है लेकिन इस के पीछे जो भावना है, वह यही है कि गरीब और कमजोर वर्गों के बीच से बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए और उन को रोजगार मिलना चाहिए।

श्रीमान् इसके साथ हमारी सरकार ने फूड फार वर्क की योजना चलाई है और दूसरी बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिन से गरीबों को रोजगार मिले। इस संबंध में हमारे साथी ने जो संकल्प रखा है उसके बारे में उनकी जो भावनाएं है, मैं उन की कद्र करता हूं लेकिन उन्होंने भू-सेना का जो सुझाव दिया है, मेरी गुस्ताखी के लिए माफी दी जाए अगर मैं यह कहूं कि भू-सेना से सब बड़े बड़े लोग जुड़ने लगे हैं। बिहार में जो भू-सेना है उससे बड़े बड़े भूपति और जमींदार जुड़े हुए हैं और उनका काम यह है कि गरीबों और मजदूरों को मारा पीटा जाए, उनको उनकी जमीन से बेदखल किया जाए, उनकी हत्या की जाए, उनकी बहिन-बेटियों की अस्मत लूटी जाए। बेहतर होता कि इसका कोई अच्छा सा नाम दिया जाता। भू-सेना के नाम से तो आज मजदूर और गरीब वर्ग में कंपकंपी छूट जाती है। इस लिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे भूसेना की बजाय इसे कोई दूसरा नाम दें तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे मैं माननीय सदस्य की भावना की कद्र करता हूं।

श्रीमन्, बेरोजगारी दूर करने के लिए हमारी प्रधान मंत्री जी ने ऐसे शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो कि प्रशिक्षण प्राप्त कर के आते हैं एक योजना चलाई है। उन

को रोजगार के लिए 25-25 हजार रुपए देने की योजना चलाई है। ऐसे शिक्षित बेरोजगारों को यह रुपया मिल भी रहा है और वे अपना काम चला रहे हैं। हमारे देश में जो बी० ए० या एम० ए० पास कर लेता है, वह यह चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले लेकिन सरकार इतनी अधिक नौकरियां उनके लिए कहां से ला सकती है। इसीलिए हमारी सरकार ने उनको रोजगार-धंधा चलाने के लिए 25-25 हजार रु० देने की योजना चलाई है और इस योजना से शिक्षित बेरोजगार लाभान्वित हो रहे हैं। यह मैं मानता हूं कि सका कुछ दुरुपयोग भी हो रहा है।

हमारी सरकार ने, जहां पहले जिला हैड-क्वार्टर तक ही बैंक थे, अब तहसील हेड-क्वार्टर और गांवों तक बैंकों का जाल बिछा दिया है। हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लीड बैंक ग्रामीणों को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं और वहां बेरोजगारों को रोज-गार भी मिल रहा है।

एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में वैसे तो छोटे-छोटे और कुटीर उद्योग बहुत बड़ी तादाद में हैं लेकिन इनको और भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन छोटे-छोटे और कुटीर उद्योगों को अनुदान भी ज्यादा मिलना चाहिए और सरकार को ऐसी हिदायतें देनी चाहिएं कि जिन देहातों में जिस तरह के उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध है, वहा उसी पर आधारित छोटे-छोटे और कुटीर उद्योग स्थापित किये जाएं। उन उद्योगों को सरकार की ओर से भरपूर सहायता दी जानी चाहिए जिससे कि ग में बेरोजगारी दूर हो।

यह जो सौ रुपये देने की बात कही गई है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। अगर किसी बेकार को जिसके कि बाल-बच्चे हैं सौ रुपया दिया जाता है तो उससे उसका गुजारा कैसे हो सकता है। बिना परिवार वाले व्यक्ति का भी इससे गुजारा नहीं हो सकता है। इससे लोगों में शिथिलता और आयेगी। इससे बेकार लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है। इसकी जगह तो उस राशि से, जितनी कि सौ-सौ रु० देने में लगेगी, इंडस्ट्री या कारखाना लगाया जाए और उसमें उन बेरोज-गार लोगों को काम दिया जाए। इससे बेकार लोगों का अधिक भला होगा।

पहले अक्सर यह देखा जाता था कि एम्पलाएमेंट एक्सचेंज जिला हेडक्वार्टर तक ही हुआ करते थे। अब बड़ी बड़ी तहसीलों में एम्पलाएमेंट एक्स चेंज खोल दिये गये हैं। मैं चाहता हूं कि ये रोजगार कार्यालय तालुका हेडक्वार्टर तक खोले जाएं और जो वहां बेरोजगार हों, उन के वहां नाम लिखे जाएं। क्योंकि गरीब लोग दूर रोजगार कार्यालयों में अपना नाम लिखाने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं और वे नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं।

इस सदन में अरसे से हमारी शिक्षा प्रणाली के दूषित होने की चर्चा चली आ रही है। हमारी शिक्षा दूषित है। इसके विषय में एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब बच्चा स्कूल में दाखिल हो तो उस वक्त यह देखा जाए कि बच्चे का दिमाग किधर जा रहा है। कोई उद्योग की तरफ जाना चाहता है, मेकेनिक बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि वह अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ सके। आज एम० ए० और बी० ए० करने के बाद रोजगार के लिए घूमते हैं। विदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं। आज

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

हमारे यहां से मेन पावर एक्सपोर्ट हो रही है। इंजिनियर और डाक्टर भी बाहर जा रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि इन सब को अपने ही देश में काम मिल सके और इनकी सेवाओं का लाभ देशवासी उठा सकें।

अक्सर यह देखा गया है कि पब्लिक अंडर-टेकिंग्स बड़े बड़े शहरों में होते हैं। मेरा सुझाव है कि सरकारी क्षेत्र के जितने कार-खाने खोले जाएं वे पिछड़े इलाकों में खोले जाएं, दूरदराज के इलाकों में खोले जाएं जहां से बेरोजगार मजदूर लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी जब कोई लायसेंस दिया जाए तो उसमें यह शर्त होनी चाहिए कि वे कारखाना पिछड़े इलाके में ही खोलें। आज यह हो गया है कि गाजियाबाद बढ़ेगा तो गाजिया-बाद ही बढ़ता जाएगा। फरीदाबाद में इंडस्ट्री लगेगी तो फरीदाबाद में ही लगती जाएगी। इस भेड़चाल को बद किया जाना चाहिए। आज बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बहुत आवश्यकता है। वहां पर उद्योग लगने से वहां के लोगों को रोज-गार के लिए हरियाणा या पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। उनको वहीं रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। अभी हमारे साथी ने बिल्कुल ठीक बताया कि रोजगार कार्यालयों में आजकल बहुत भ्रष्टाचार है। वे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। वहां पर नाम लिखाइए वर्षों बीत जाते हैं लेकिन कार्ड नहीं निकलता। कई लोग तो ओवर एज हो जाते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता। इस ओर तवज्जह देने की आवश्यकता है। इस भ्रष्टा-चार को समाप्त किया जाना चाहिए। जो लोग पैसा देते हैं उनका कार्ड निकल आता है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, आज बेरोजगारी एक विकट समस्या है। हमारे नेगी जी ने जो संकल्प पेश किया है, वस्तुत: वह समाचीन है। इस पर बराबर चर्चा होती रहती है, लेकिन बेरोजगारी सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है। हमारे करोड़ों नौजवान इसमें समा रहे हैं और आज देश में एक बेरोजगारों की फौज बन रही है। इससे सारे देश की अर्थ-व्यवस्था लड़खड़ा रही है। इसके साथ-साथ अराजकता और अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार और अपराध कर्म भी बढ़ रहे हैं। आजादी प्राप्त हुए 37 साल हो गए हैं लेकिन आज भी मैट्रिक और उससे आगे की शिक्षा प्राप्त कर करीब दस करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तथा पांच से अधिक टैक्नोक्रेट्स बेकार हैं। इन लोगों को काम में लगाने के लिए हमारे पास सुनियोजित प्लानिंग नहीं है। इतनी पंचवर्षीय योजनाएं बन रही हैं और उन पर अरबों-खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन पता नहीं यह सब कहां चले जाते हैं? बेरो-जगारों की संख्या फिर भी दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही चली जा रही है। केवल योजनाएं बन रही हैं और भाषण हो रहे हैं। भोजनम् भाषणम् और उद्घाटनम हो रहे हैं लेकिन जमीन पर उनका ट्रांसलेट नहीं हो रहा हैं। जमीन पर अनुवाद कराने के लिए आपके पास ताकत नहीं है। अगर आप इस देश की राष्ट्रीयता की भावना से इस देश को ऊपर

उठाने की ओर सोचें तो यह काम हो सकता है। छठी पंचवर्षीय योजना में 1983-84 के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए दस हजार करोड़ रुपया अलाट किया गया। तकरीबन दस हजार प्रखण्ड हैं और हर प्रखण्ड के लिए दो करोड़ रुपया दिया जाता है। ईमानदारी से यह रुपया अगर प्रत्येक प्रखंड में जाता तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता था। पैसे का जो डायवर्सन होता है, वह केवल कागजों तक ही सीमित रहता है, जनता तक नहीं पहुंच पाता। इसके लिए गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। दलगत भावना से ऊपर उठकर ही काम करना चाहिए। हमारे देश के जितने भी बढ़े बड़े मनीषी जैसे महात्मा गांधी या लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हुए हैं, देश की जनता को सुख पहुंचाने की उनकी भावना रही है। सब के लिए समानता, भाईचारा और न्याय यह संविधान में लिखा था। यह सब किताबों में ही लिखा हुआ है। प्रतिदिन हत्याएं और लड़ाइयां हो रही हैं। वीकर सैक्शन के इंटरेस्ट को नेगलेक्ट किया जा रहा है। छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है। उसी प्रकार से दस करोड़ लोग ही साठ करोड़ लोगों के इंटरेस्ट को नेगलेक्ट कर रहे हैं। कृषि प्रधान देश का मुख्य धंधा कृषि है। इसलिए, डिफेंस के बाद ज्यादातर पैसा कृषि पर खर्च किया जाना चाहिए। अगर जनसंख्या का घनत्व देखें तो प्रत्येक किलोमीटर का 375 बैठता है। यदि कृषि, सिंचाई, लघु-उद्योग और औद्योगिकरण का युद्ध स्तर पर कार्य होता तो आज 38 प्रतिशत जो नजारा हमें देखने को मिल रहा है, वह न होता। लेकिन, आज आरक्षण के लिए लड़ाइयां हो रही हैं तथा अनुसूचित जातियों के अधिकारों को छीना जा रहा है। मारा मारी चल रही है, अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, हर तरह की लड़ाइयां यहां हो रही हैं। यह सब केवल बेईमानी के बंदरबाट के कारण हो रहा है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। यह सब ऊपर से नीचे तक, बड़े बड़े नेताओं से लेकर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की नीतियों का परिणाम है क्योंकि उन्होंने ये योजनायें कागजों पर ही हैं, इनको धरती पर नहीं उतारा है। बीस सूत्री कार्यक्रम की बड़ी चर्चा है। उसकी रूपरेखा आपने बनाई है। मैं गांवों से आता हूं। मैंने देखा है कि बीस सूत्री विकास कार्यक्रम की रूपरेखा न बन कर यह केवल भ्रष्टाचार की रूपरेखा मात्र हो गई है। जो पैसा गांवों में जाता है वह फिर शहरों की ओर वापिस आ जाता है। वह केवल अधिकारी वर्ग के अन्दर ही घूम रहा है। गरीबों तक वह नहीं पहुंच रहा है। ईटिंग, सीटिंग, मीटिंग एंड चीटिंग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आपने कार्यान्वयन समितियां बनाई हैं। उन में केवल एक दल के लोगों को ही आप ने रखा है। अगर यह राष्ट्रीय प्रोग्राम है तो इस में सभी दलों के लोगों को आपको रखना चाहिए था और उनका सहयोग लिया जाना चाहिए था। सभी की भलाई के लिए यह कार्यक्रम है तो सभी का सहयोग इसके लिए लिया जाना चाहिये था।

PROF. N.G. RANGA: You are also a Member of the District Committee. Every Member of Parliament is associated with one or the other of the District Committee. The District authorities have to consult you. You are members of the Committee. If there is anything wrong, there must be something wrong with you also. Don't make a generalisation. ... All of us are associated. MLAs are also associated. All Parties are associated.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अभी तक दूसरी पार्टियों का इस में समावेश नहीं किया गया है। प्रखंड लेवल पर उनको नहीं बुलाया जाता है। हम विदेशी नहीं हैं। हम भी इस देश के वासी हैं, दूसरी पार्टियों के लोग भी इस देश के वासी हैं। बेहतर होता अगर सभी दलों को इन समितियों में रखा जाता। मेरे पास एक पत्र आया है। इस में टास्क फोर्स की बात कही गई है। जिला उद्योग केन्द्र के पदाधिकारी द्वारा लिखा गया है कि सैंट्रल गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स नियुक्त की है और उसके द्वारा जिस को रिकोमेंड किया जाएगा, जिस की अनुशंसा होगी उन्हीं को जो पच्चीस हजार रुपया है वह दिया जाएगा। इसके लिए दो आदमियों को रिकोमेंड किया गया। इस तरह से काम नहीं चल सकता है। इसका मतलब है कि जो आपके दल में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, चाहे वे काम करें या न करें उन्हीं के लिए और उन्हीं के हित के लिए यह चीज है। इससे राष्ट्र का हित नहीं होता।

सभापति महोदय : आपका समय हो चुका है। आपकी पार्टी ने डबल समय ले लिया है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : यह पार्टी का सवाल नहीं है। मैं खत्म कर रहा हूं। आलोचना के बाद अब मैं सुझाव देना चाहता हूं।

हमारा कृषि प्रधान देश है। कृषि की उन्नति युद्ध स्तर पर की जानी चाहिए थी और उसके लिए योजना बनाई जानी चाहिए थी। इससे करोड़ों लोगों को काम मिल सकता था। अब भी आप इसको कर सकते हैं। पहले नारा भी दिया गया था कि हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। श्री नेगी ने यह भी कहा है कि नदियों का विस्तार किया जाए। यह भी बहुत अच्छा सुझाव है। एक नदी को दूसरी से जोड़ा जाए। छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं को हाथ में लेना चाहिये। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाना चाहिए। ये सब काम हमें युद्ध स्तर पर करने चाहिये। आज तक कितनी सिंचाई सुविधायें उपलब्ध आप कर पाए हैं, इसको आप देखें। आंध्र 36 प्रतिशत, असम 17 परसेंट, बिहार 33 परसेंट, गुजरात 19 परसेंट, केरल 12 परसेंट, मध्य प्रदेश 11 परसेंट, महाराष्ट्र 12 परसेंट, उत्तर प्रदेश 44 परसेंट। 38 बरस में 12-13 परसेंट जमीन की सिंचाई होती है तो आप सोच सकते हैं कि 70 करोड़ की फौज जो सारे देश में है, उसको भोजन आप वहां से दे सकेंगे। इसमें लाखों करोड़ों मजदूरों को काम मिल सकता था। अगर हम नहरें बनाते, सिचाई के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते और जितने भी प्राकृतिक नदी-नाले हैं उसमें लिफ्ट इरिगेशन का प्रयोग करते तो उससे बहुत सी जमीन में सिंचाई होती, हर खेत में पानी पहुंचता, लेकिन यह नहीं हो पाया।

छोटा नागपुर में लोहा, अभरक, तांबा, बौक्साइट बहुत मात्रा में मिलता है। सारे हिन्दुस्तान का यह बहुत बड़ा मिनरल बैल्ट है। वहां की जमीन में कुल मिलाकर 4.7 प्रतिशत तक ही सिंचाई हो पाई है। जहां से अरबों, खरबों रुपया प्रतिवर्ष सारे देश के लिए मिल रहा है, वहां इस प्रकार की दुर्व्यवस्था, हो यह देखने की बात है।

1983-84 में आपने 2.13 मिलियन टन गेहूं का इम्पोर्ट किया है और 5.7 लाख टन चावल का इम्पोर्ट किया है जिस पर आपने

335 करोड़ रुपया लगाया है । 600 से 800 करोड़ का हमने खाद्य तेल और दालों का इम्पोर्ट किया है । हमारा इतना बड़ा विशाल देश है अगर इस राशि का 50 प्रतिशत भी हम कृषि भूमि की सिचाई के लिए उपयोग करते तो कितना अनाज देश में लोगों को मिल सकता था और करोड़ों लोगों को काम मिल सकता था । डिफेंस के बाद दूसरी बड़ी राशि हमें खेती के लिये खर्च करने की जरूरत है ।

मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं । हर आदमी को काम कैसे मिले, इसके लिए इस तरह से योजना बनाई जाये कि हर प्रखंड में कम से कम 10 मध्यम उद्योगों की ईकाई लगाई जाये जिससे ढाई-तीन हजार आदमियों को काम मिल सकेगा । इस तरह से बहुत से बेरोजगारों को काम मिल सकता है । हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में आश्वासन दिया था कि हम इस तरह का इन्फास्ट्रक्चर बनायेंगे जिससे देश का उद्योगीकरण होगा हर संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक मदर इंडस्ट्री लगानी चाहिए । किसी एक क्षेत्र में ही सारी इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहियें ।

अगर पंचायती राज्य हमने कायम किया है तो पंचायतों में ही यह योजनाएं बननी चाहियें । पंचायत समितियों में एक प्रखंड में इस पर पंचायत के मुखिया विचार कर सकते हैं न कि दिल्ली में बैठकर योजनाएं बनाई जाये । यहां उल्टा चल रहा है । आई० ए० एस० अफसर जो कभी गांव में रहे नहीं, दिल्ली में बड़े-बड़े एयर कंडीशंड कमरों में बैठकर योजनाएं बनाते हैं जिसमें हजारों करोड़ों रु० लगाये जाते हैं । सोने के अंडे देने वाली चिड़िया की तरह एक-एक सिंचाई की योजना बनाई जाती है ।

अन्त में मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अगर आप अन-एम्पलायमेंट को समाप्त करना चाहते हैं तो योजना का रूप बदलें । जब आप सारे देश में पंचायती राज लगाना चाहते हैं तो पंचायत समितियों में यह योजनाएं बनाइये ताकि लोगों को काम मिल सके ।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, आपने जो समय दिया है, इसके लिए लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और साथ ही साथ श्री नेगी जी ने जो अन-एम्पलायमेंट के बारे में यहां अपना रेज्यूलूशन मूव किया है, उसका भी समर्थन करती हूं क्योंकि देश में अन-एम्पलायमेंट बढ़ती जा रही है ।

हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस बारे में बहुत प्रोग्राम दिये हैं । डी० आर० डी० ए०, आई० आर० डी० पी०, डी० डी० पी०, एन० आर० एफ० पी० और सेल्फ एम्पलायमेंट फार एजूकेटेड अन-एम्पलायड यूथ के लिए बहुत से प्रोग्राम दिये जा रहे हैं । जो भी प्रोग्राम दिये गये हैं, मैं यही कहना चाहती हूं कि ये लोगों के पास जाने चाहियें । ऐसा करने से ही सब को एम्लायमेंट मिलेगा । यह कोई पोलीटिकल प्राबलम नहीं हैं, बल्कि एक सामाजिक प्राबलम है । लोगों को एम्पलायमेंट देने के लिए बहुत से प्रोग्राम हैं । प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को एजूकेटिड अनएम्पलाय्ड के लिए एक प्रोग्राम एनाउंस किया था । उसके अन्तर्गत

[श्रीमती विद्या चेन्नुपति]

25 000 रुपए का लोन दिया जाता है और 25 परसेंट सबसिडी है। लेकिन इस बारे में प्राबलम एक ही है कि लोन और ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन मार्केटिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक एफारस्टेशन प्रोग्राम का संबंध है, मेरी कांस्टीट्युएन्सी में एक गांव वेलवेडम है, जहां चार पांच सौ लोग पिछले चालीस साल से 400 एकड़ जमीन को कल्टीवेट कर रहे हैं। एफारस्टेशन प्रोगाम के आफिसर्ज उस जमीन को छीनना चाहते है। मैंने उनसे कहा कि जो लोग खेती करते हैं, अगर उनको पट्टा न दें सकें, तो लीज बढ़ा सकते है। इस प्रोग्राम के बजट में पौधों को पानी देने के लिए बजट में व्यवस्था नहीं की गई है। यह आवश्यक है कि पानी पहुंचाने के लिए वोर-वेल्ज तैयार किए जाएं। इनके अलावा एफारेस्टेशन प्रोग्राम में सिर्फ एक आदमी को नहीं, बल्कि पूरे फैमिली को इन-वाल्व करना चाहिए और उसके जरिये एम्पलायमेंट के अवसर जेनीरेट करने चाहिए।

महिलाओं को एम्पलायमेंट देने के लिए प्रोग्राम बनाना चाहिये। अगर महिलाएं केवल रोटी बनाकर बाकी समय बेकार बैठी रहें, तो समाज को कोई लाभ नहीं होगा। अगर महिलाओं को भी कुछ पैसा कमाने की सुविधा दी जाए तो उससे परिवार की आमदनी में वृद्धि होगी। डी० आर० डी० ए० प्रोग्राम के अन्तर्गत स्माल-स्केल इंडस्ट्री और काटेज इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग और स्टाइपेंड दिया जाए और उसके बाद मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए।

एम्पलायमेंट देते हुए इकानोमिक बैकवर्डनेस का ध्यान रखना चाहिए। कई कम्युनिटीज में इकानोमिक बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा हैं। उनमें अच्छे कार्यकर्त्ता मिल सकते हैं। और अपने आप अपने पांवों पर खड़े होने के लिए उन को कुछ काम दें। यह सारी फेमिली के लिए काम हो सकता है। उस से ये बेगारी कम हो जायगी। नहीं तो बेगर्स आज बढ़ते जा रहे हैं। यह एक प्रोफेशन हो गया है। हर एक आ कर पैसा मांगने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए उन को कुछ काम दिलवाना चाहिए, नहीं तो यह प्राबलम बनी रहेगी।

हन्ड्रेड डेज का कुछ इंसेटिव प्रोग्राम आप ने रखा है। हन्ड्रेड डेंज में तीन महीने दस दिन होते हैं। तीन महीने में कैसे यह हो सकता है? तीन महीने में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। इसलिए कम से कम एक साल का यह होना चाहिए। हन्ड्रेड डेज के बजाय इसे वन ईयर का कर देना चाहिए जिस से जो भी प्रोग्राम आप देते हैं उस से जो भी प्रोग्राम आप देते हैं उससे लोगों को मदद मिल सके

पहाड़ों के ऊपर आप पेड़ लगाना चाहते है। पेड़ लगाते हैं लेकिन उस को पानी देने के लिए हम नहीं सोचते हैं। मैं यह देख रही हूं कि यह एफारेस्टेशन प्रोग्राम जहां जहां भी चलते हैं वहां पानी देने के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। मैं यह सलाह देती हूं कि जहां पेड़ आप लगाते हैं और पेड़ों का पालन करना चाहते हैं वहां पानी कहां से आएगा, यह पहले सोच लें। जहां पानी नहीं आ सकता वहां यह एफारेस्टेशन प्रोग्राम जो आप चला रहे हैं वह कभी सकसेसफुल नहीं हो सकता है। यह प्रोग्राम कागज पर तो रहेगा लेकिन पेड़ वहां नहीं तैयार होंगे।

.. (व्यवधान) मैं तो सिर्फ प्वाइंट रख रही हूं. कोई भाषण नहीं दे रही हूं। मेरी कांस्टीच्यूएंसी में पहाड़ है, मैं ने देखा है वहां पेड़ लगाते हैं लेकिन पानी डालने वाला कोई नहीं होता है। इस में सेल्फ एम्पलायमेंट स्कीम बन सकती है अगर आप पेड़ रखने के लिए कुछ पैसा दे दें और फिर उस को पानी देने लिए कुछ पैसा दे दें।

यह जो खादी ऐंड विलेज इंस्ट्रीज का प्रोग्राम है इस को हर एक गांव में ले जा सकते हैं लेकिन गांव वालों तक इस को नहीं ले जा रहे। इस को गांव गांव तक ले जाने की कोशिश करनी चाहिए।

इसी तरह कैनाल बन्ध्स की स्कीम है। उस में एफारेस्टेशन का प्रोग्राम हम ले रहे है। उसमें जो अनएजूकेटेड यूथ्स होते हैं उन को फेमिली प्रोग्राम के अन्तर्गत ले कर यह काम हम उन को देखें तो उस के जरिए उन को एम्पलामेमेंट मिल सकता है। इस तरह हम जो उन की मदद करने के लिए तैयार है वह मदद उन को मिल जायेगी। इन सारे प्वाइंटस को मंत्री महोदय सोचें और इस के अनुसार कार्यवाही कर के उन को मदद पहुंचाएं। जो भी मदद हम करना चाहते है वह मदद गरीबों तक पहुंचनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है। आप ने जो समय दिया उस के लिए धन्यवाद देती हूं और यह जो प्रस्ताव है उस का मैं समर्थन करती हूं।

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Abdul Rashid Kabuli.

(*Interruptions*)

MR CHAIRMAN :Hon. Members, all parties have had their share, After Mr. Kabuli, I will ask the Minister to give his reply.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): इस पर टाइम बढ़ा दिया जाय जिस से सभी माननीय सदस्यों को मौका मिल सके।

श्री राम विलास पासवान : यह इतना इम्पोर्टेंट मसला है, इस पर टाइम बढ़ना चाहिये।

MR. CHAIRMAN : Whatever has been decided by the House has to be adhered to. If the House wants time can be extended. Now, you yourself will admit that one hourh as been extended. You yourself will admit that the Minister has to reply.

(*Interruption*)

SHRI RAM VILAS PASWAN : You said that we would decide about the extension of time for this Rosolution after one hour Now, Mr. Chairman, you please ask the wishes of the House for the extension of time for this Resolution.

SEVERAL HON. MEMBERS : The time for discussion and consideration of this Resolution may be extended by one hour. This is an important Resolution.

MR. CHAIRMAN : If the wish of the House is like that, then we will extend the time for this Resolution. But I would like to suggest one thing, that is, we will complete the discussion by the Members from both the sides and at 5.30 p.m. I will call the Minister to reply to the debate. I would therefore make it clear to the Hon. Members that they may kindly be brief in their submission. Now, Mr. Kabuli may speak.

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाब चेयरमैन साहब, जो प्रस्ताव इस वक्त लोकसभा के सामने पेश है. मैं उसकी हिमायत में खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि आज हमारे मुल्क में सबसे बड़ी समस्या जो है वह यही है कि हमारे करोड़ों लोग बेकार हैं और उनकी तादाद में लगातार इजाफा

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

होता जा रहा है। आज देहाती क्षेत्र में करीब तीन करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार का कोई वसीला नहीं है। राष्ट्रपति जी ने पार्लियामेंट के सामने अपनी जो तकरीर पेश की थी उसमें उन्होंने बताया है कि हर साल करीब पांच लाख लोगों को सरकार रोजगार दिलाने में मदद करेगी। इस बात से ही आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह जो प्राब्लम है इसका हल कितना मुश्किल होगा। आज न सिर्फ देहाती क्षेत्र में अनपढ़ बेरोजगार लोगों की तादाद ही बढ़ती जा रही है बल्कि शहरों में पढ़े-लिखे नौजवानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और वे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं समझता हूं सरकार का यह फर्ज बनता है कि वह जो भी मंसूबाबंदी करे उसमें इस बात का खास तौर से ख्याल रखे।

आज जो सेल्फ-इम्पलायमेंट की स्कीम चालू हुई है मैं समझता हूं उससे लोगों को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा है। आप नौजवानों को कुछ कर्जा या बाकी और फैसिलिटीज देते है उसमें जो इन्ट्रेस्ट वाजिब अदा होता है उसके सिलसिले में उन लोगों को इतनी दिक्कतें पेश आती हैं जिसकी वजह से यह स्कीम फेल्योर साबित हो रही है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि मुल्क में एक बहुत बड़ा स्कैंण्डल इस सेल्फइम्पलायमेंट स्कीम चल रहा है। इस स्कीम में जितना इन्बेजिलमेंट हो रहा है उसकी कोई इन्तहा नहीं है। इसी वजह से यह स्कीम बजाय फायदे के नुकसान में जा रही है और मुल्क के नौजवानों को भी कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है।

बेरोजगारी को खत्म करने के सिलसिले में जैसा कि आज के इस प्रस्ताव में कहा गया है, दरियाओं की खुदाई, नदी-नालों की खुदाई और जंगलात बढ़ाने के सिलसिले में लाखों करोड़ों लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता है और इस तरह से उनको रोजगार मोहैया किया जा सकता है। आज इस मुल्क में जनशक्ति सबसे बड़ी चीज है। मुझे माफ किया जाए मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमारे मुकाबले मे रूस और चीन ने अपनी जनशक्ति का बेहतर इस्तेमाल किया है। चीन तो हमसे बाद में आजाद हुआ लेकिन उस ने बड़े अच्छे ढंग से मंसूबे के तहत अपनी जनशक्ति का फायदा उठाया। उस देश ने जन शक्ति का बहुत अच्छा फायदा उठाया है। वे पहाड़ जहां पर पहुंचना मुश्किल था, उनको काट कर रास्ते बनाए गये और वहां की खुराक बढ़ाने के लिये इस्तेमाल किया गया। वह काम डिटरमिनेशन के तहत, हौंसले के साथ एक खास प्लानिंग के तहत उस मुल्क में हुआ। उसके मुकाबले में हम बहुत पीछे रहे।

मैं आपको बताना चाहता हूं; यह प्रस्ताव में कहा गया है कि जंगलात को फिर से खड़ा करने के सिलसिले में काम किया जाए। इस बात से जाहिर होता है कि हमारे देश में एक्सप्लायटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं जिस स्टेट से ताल्लुक रखता हूं, वहां जंगलात का सबसे बड़ा खजाना है। 1947 से आजादी के बाद देश में बड़े-बड़े महल खड़े किये गये, लेकिन जंगलात का सफाया कर दिया गया। जंगल तबाह हो चुके हैं। यह सवाल सिर्फ मेरी स्टेट का नहीं है, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यह मसला पूरे हिन्दुस्तान का मसला है। जंगलों के काटने से सारा इन्वायर्नमेंट तबाह हो गया है। जिस की वजह से मुल्क को हर साल बाढ़ और

दूसरी किस्म की तबाही का सामना करना पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि देश की जनशक्ति का फायदा उठाने की कोशिश की जाए और जंगलों के काटने का सिलसिला बंद हो, लेकिन जंगल को बढ़ाने का कोई सामान हो तो उसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस मसले को गंभीर मसला जानकर अपने हाथ में ले। जंगलों को फिर से अपने पांव पर खड़ा करें। अपने पांव पर खड़ा करने के लिये देश की करोड़ों-लाखों बेरोजगार जनशक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है।

मैं आपकी मारफत यह भी कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के वक्त में फूड-फार-वर्क की एक स्कीम चली थी। यह सही है कि उस जमाने में भी करप्शन हुआ। मजदूरों की मेहनत का कुछ लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। उनके नाम से अपनी जेबों को भरा यहां तक कि मिनिस्टरों ने भी इस काम को किया। जो जनता पार्टी के वक्त में हुआ, वह आज भी हो रहा है और कल भी हो सकता है। यह इसलिए हो रहा है कि हमने उस सिस्टम को नहीं बदला है। एक कारण यह भी है कि ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में बहुत ज्यादा पावर्स चली गई है। ब्यूरोक्रेट्स पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वे लोगों के सामने जवाबदेह नहीं हैं। उन्होंने अपने एम्पायर्स खड़े कर रखे हैं। जो कुछ हुआ, वह आज भी होगा और कल भी हो सकता है। इस तरीके से सरकार जो कुछ भी सहायता उनकी करना चाहती है, लोगों को रोजगार मिले, वह हो नहीं पा रहा है। इन सब चीजों के लिए सिस्टम भी जिम्मेदार है और इस सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा। हमने सरमाएदार निजाम की फौकियत दी है। हमने अपने हाथों से इसे अपने सर पर मुसल्लत कर दिया है। आजादी के वक्त टाटा बिरला और बड़े-बड़े पूंजी पतियों की जायदाद 10-12 करोड़ की थी, लेकिन स्वराज्य आने के बाद उनकी जायदाद अरबों रुपयों की हो गई है। इन सरमाएदारों ने मुल्क की कौमी दौलत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिस की वजह से अमीर और गरीब के बीच में एक खाई पैदा हो गई है। सरकार भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकती है कि हमारी आबादी का 50 प्रतिशत हिस्सा आज भी बिलो-सबसिसटैंस लैवल की जिन्दगी गुजर कर रहा है। इस से बढ़ कर बदनसीबी क्या हो सकती है कि इतना बड़ा उत्पादन हो रहा है, इतनी टैक्नोलाजी और साइन्टिफिक मीन्ज हम ने इस्तेमाल किये हैं, मुल्क आगे बढ़ा है, लेकिन उस के बावजूद इस का फायदा बहुत कम लोगों को जा रहा है, अक्सरियत को फायदा नहीं मिल रहा है। इसी लिये मैंने कहा है कि जो स्कीमें बनें, जो चर्चा यहां करें, जो प्लानिंग हो, उस में प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिये कि उस में हम किन को फायदा देना चाहते हैं। इसके लिये जरूरत है कि जो हमारी सब से बड़ी आबादी देहातों में रह रही है, शहरों में जो बेकार लोग हैं, उन को इस प्लानिंग के जरिए सब से ज्यादा फायदा दिया जाय। यह जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की है। यह जिम्मेदारी आप की है। हमारा यह दावा रहा है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है इस का फायदा आम लोगों को जायगा और हमारा यह अभिमान रहा है कि हम सोशलिस्टिक स्टेट कायम करना चाहते हैं लेकिन वह अभी तक कागज पर ही है, उस पर अमल नहीं हो रहा है। इस लिये जो हमारे तीन करोड़ लोग आज बेकारी की जिन्दगी गुजार रहे हैं, लाखों बेकार नौजवान जो एम० ए० और पी० एच० डी० हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, जब तक उन का मसला हल नहीं करेंगे तब तक इस मुल्क में सोशलिज्म लाने का जो आप का कमिटमेन्ट है, वह पूरा नहीं होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि सिस्टम में तबदीली लाई जाय।

इन अल्फाज के साथ मैं इस प्रस्ताव का मुकम्मिल तौर पर हिमायत करता हूं।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) جناب چیئرمین صاحب جو پرستاو اس وقت لوک سبھا کے سامنے پیش ہے میں اسکی حمایت میں کھڑا ہوا ہوں - میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ملک میں سب سے بڑی سمسیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے کروڑوں لوگ بیکار ہیں اور انکی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے - آج دیہاتی چھیتر میں قریب تین کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس روزگار کا کوئی وسیلہ نہیں ہے - راشٹرپتی جی نے پارلیمنٹ کے سامنے اپنی جو تقریر پیش کی تھی اس میں انھوں نے بتایا ہے کہ ہر سال قریب پانچ لاکھ لوگوں کو سرکار روزگار دلانے میں مدد کرے گی - اس بات سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو پروبلم ہے اس کا حل کتنا مشکل ہوگا - آج نہ صرف دیہاتی چھیتر میں ان پڑھ بے روزگار لوگوں کی تعداد ہی بڑھتی جا رہی ہے بلکہ شہروں میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں - میں یہ سمجھتا ہوں سرکار کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جو بھی منصوبہ بندی کرے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھے -

آج جو سیلف ایمپلائمینٹ کی اسکیم چالو ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے لوگوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا ہے - آپ نوجوانوں کو کچھ قرض یا باقی اور فیسیلیٹیز دیتے ہیں اس میں جو انٹرسیٹ واجب الادا ہوتا ہے اسکے سلسلے میں ان لوگوں کو اتنی دقتیں پیش آتی ہیں جسکی وجہ سے یہ اسکیم فیلیور ثابت ہو رہی ہے - بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ملک میں ایک بہت بڑا اسکنڈل اس سیلف امپلائمینٹ اسکیم میں چل رہا ہے - اس اسکیم میں جتنا امبیزلمینٹ ہو رہا ہے اسکی کوئی انتہا نہیں - اس وجہ سے یہ اسکیم بجائے فائدے کے نقصان میں جا رہی ہے اور ملک کے نوجوانوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے

بے روزگاری ختم کرنے کے سلسلے میں جیسا کہ آج کے اس پرستاو میں کہا گیا ہے - دریاؤں کی کھدائی ندی نالوں کی کھدائی اور جنگلات بڑھانے کے سلسلے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے آج اس ملک میں جن شکتی سب سے بڑی چیز ہے - مجھے معاف کیجئے مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ ہمارے مقابلے میں روس اور چین نے اپنی جن شکتی کا بہت استعمال کیا ہے - چین تو ہم سے بعد میں آزاد ہوا لیکن ان نے بڑے اچھے ڈھنگ سے منصوبے کے تحت اپنی جن شکتی کا فائدہ اٹھایا -

اس دیش نے جن شکتی کا بہت اچھا فائدہ اٹھایا ہے - وہ پہاڑ جہاں پر پہنچنا مشکل تھا انکو کاٹ کر تختے بنائے گئے اور وہاں کی خوراک بڑھانے کے لئے اسکا استعمال کیا گیا - وہ کام ڈٹرمینیشن کے تحت حوصلے کے ساتھ ایک خاص پلاننگ کے تحت اس ملک میں ہوا اسکے مقابلے میں ہم بہت پیچھے رہے ہے - میں آپکو بتانا چاہتا ہوں - یہ پرستاو ن میں کہا گیا ہے کہ جنگلات کو پھر سے کھڑا کرنے کے سلسلے میں کام کیا جائے -

اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے دیش میں ایکسپلائیٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے - میں جس اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہوں وہاں جنگلات کا سب سے بڑا خزانہ ہے - ۱۹۴۷ء سے آزادی کے بعد دیش سے بڑے بڑے محل کھڑے کئے گئے لیکن جنگلات کا صفایا کر دیا گیا - جنگل تباہ ہو چکے ہیں یہ سوال صرف میری اسٹیٹ کا نہیں ہے ہماچل پردیش کا ہو -

اتر پردیش ہو یہ مسئلہ پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے جنگلوں کے کاٹنے سے سارا اینوائرمینٹ تباہ ہو گیا ہے - جس کی وجہ سے ملک کو ہر سال باڑھ اور دوسری قسم کی تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے -

ضرورت اس بات کی ہے کہ کی جن شکتی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے اور جنگلوں کے کاٹنے کا سلسلہ بند ہو لیکن جنگل کو بڑھانے کا کوئی سامان ہو تو اسکے لئے ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی۔ اسلئے میں چاہوں گا کہ اس مسئلے کو گمبھیر مسئلہ جانکر اپنے ہاتھ میں لیں۔ جنگلوں کو پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لئے دیش کی کروڑوں لاکھوں بے روزگار جن شکتی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔

میں آپ کی معرفت یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جنتا پارٹی کے وقت میں فوڈ فار ورک کی ایک اسکیم چلی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ اس زمانے میں بھی کرپشن ہوا۔ مزدوروں کی محنت کا کچھ لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ان کے نام سے اپنی جیبوں کو بھرا یہاں تک کہ منسٹروں نے بھی اس کام کو کیا۔ جو جنتا پارٹی کے وقت میں ہوا وہ آج بھی ہو رہا ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو نہیں بدلا ہے ایک کارن یہ بھی ہے کہ بیوروکریٹس کے ہاتھ میں بہت زیادہ پاورس چلی گئی ہے۔

بیوروکریٹس پر اسکی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ لوگوں کے سامنے جوابدہ نہیں ہیں انھوں نے اپنے ایمپائرس کھڑے کر رکھے ہیں۔ جو کچھ ہوا وہ آج بھی ہوگا اور کل بھی ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے سرکار جو کچھ بھی سہایتا انکی کرنا چاہتی ہے لوگوں کو روزگار ملے وہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کے لئے سسٹم بھی ذمہ دار ہے اور اس سسٹم کو بھی بدلنا پڑے گا۔ ہم نے سرمایہ دارانہ نظام کو فوقیت دی ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے اپنے سر پر مسلط کر دیا ہے۔ آزادی کے وقت ٹاٹا برلا اور بڑے بڑے بڑے پونجی پتیوں کی جائداد ۱۰۔ ۱۲ کروڑ کی تھی لیکن سوراج آنے کے بعد انکی جائداد کھربوں روپوں کی ہوگئی ہے۔ ان سرمایہ داروں نے ملک کی قومی دولت کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے جس کی وجہ سے امیر اور غریب کے بیچ میں ایک کھائی پیدا ہوگئی ہے۔ سرکار بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتی ہے کہ ہماری آبادی کا ۵۰ پرتیشت حصہ آج بھی بلو سبسٹینس لیول کی زندگی گزار رہا ہے۔

اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اتنا بڑا اتپادن بڑھ رہا ہے اتنی ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک مینس ہم نے استعمال کئے ہیں ملک آگے بڑھا ہے لیکن اسکے باوجود اس کا فائدہ بہت کم لوگوں کو جا رہا ہے۔ اکثریت کو فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ اس لئے میں نے کہا ہے کہ جو اسکیمیں ہیں جو چیزیں یہاں کریں جو پلاننگ ہو اس میں پرائیورٹی فکس ہونی چاہیئے کہ اس میں ہم کن کن فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ اسکے لئے ضرورت ہے کہ جو ہماری سب سے بڑی آبادی دیہاتوں میں رہ رہی ہے شہروں میں جو لوگ بیکار ہیں ان کو اس پلاننگ کے ذریعے سب سے زیادہ فائدہ دیا جائے۔ یہ ذمہ داری رولنگ پارٹی کی ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہمارا یہ دعوی رہا ہے کہ جو ہماری ڈیموکریسی ہے اس کا فائدہ عام لوگوں کو جائے گا۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم سوشلسٹ اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ ابھی تک کاغذ پر ہی ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اس لئے جو ہمارے تین کروڑ لوگ آج بے کاری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لاکھوں بے کار نوجوان جو ایم اے اور پی۔ ایچ۔ ڈی ہیں لیکن ان کو کام نہیں مل رہا ہے جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں کریں گے۔ تب تک اس ملک میں سوشلزم لانے کا جو آپکا کمیٹمینٹ ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ سسٹم میں تبدیلی لائی جائے۔

ان الفاظ کے ساتھ میں اس پرستاو کا مکمل طور پر حمایت کرتا ہوں

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak) : Sir, I am very thankful to you for giving me a few minutes to speak on the resolution moved by Mr Negi in this House. The unemployment problem of the country is no doubt grave, and it is assuming more and more serious proportions day by day.

I have no time to mention and repeat what hon. friends from this side and the other have mentioned. I would like to confine my observations to a few points. The hon. Members opposite have tried to blame the Government, saying that it is the responsibility of the Government or the party in power alone, to solve this problem. But I must say that this problem is not the problem of the Congress party or only of the Government in power. With the cooperation of the country as a whole, and of the hon. Members opposite, this problem can be solved.

We know under what constraints the Government is functioning. It is needless to emphasize here that this House has discussed the amounts of money spent, and earmarked in the successive five-year plans. Many Members have emphasized this in the House. So, I do not like to repeat things again in this debate. But I would like to appeal to the hon. Members and say that this problem does concern the Government alone or the party in power alone.

My friend who has moved this resolution has stressed certain points. But I must ask him : are these points going to solve this problem which has assumed such big proportions now ? They are not, because we have seen that money has been ear-marked, and spent. In spite of this, these programmes have not yielded results that we expected. In this context, I must appeal to hon. Members from both the sides and also to Government to see that whatever programmes we have kept before the country, are implemented, so that the results reach the people at the grass-roots level.

Here I would like to point out, as my hon. friends have already pointed out, that during the 6th Five Year Plan, IRDP, NREP, alongwith self-generating employment programme and many other anti-powerty programmes have been envisaged and are being implemented for the good of the people, to remove the backwardness of the people, to bring the people above the poverty line who are living below the poverty line. It has been mentioned here. But I would like to point out that the implementation is the most important and the key factor in the success of these programmes in the country I must emphasise here that howsoever good a programme may be, howsoever noble a programme may be, if it has not yielded the desired result, what is the use of its being good ? My hon. friends have pointed out that this has not been done, that has not been done and so on. I must point out to my hon. friends opposite that whenever any charge or complaint has come before the House concerning the State Government implementation machinery, certainly there was hue and cry and everybody has said that the Centre has no power to interfere in the internal matters of a State or that a particular matter is a State subject. In this context, under the Constitution, we know that the Central Government has power but that is limited and limited to the extent that it cannot interfere in the matter of a State subject. So, in this context, in this sense, we must be truthful, we must be brave enough to point out the defects which lie in the State level or the central level or the block level or the district level. We know, apart from IRDP, NREP and so many other programmes, government have also made provisions in the tribal sub-plans, in the special component plans ; and during the 6th Five Year Plan, Rs. 5,500 crores are going to be spent for the development of tribal people as well as another Rs. 500 crores for the development of SC&ST under the sub-plan programmes. But how to ensure whether the money which has been sanctioned for the purpose for which it was meant at the State level is being utilized ? It is not being done as desired in the plan. I am

going to quote from page 3 of the SC&ST Thirty-Fifth Report (Seventh Lok Sabha), Ministry of Home Affairs. It says as follows :

"The Committee are not satisfied with the reply of Planning Commission which shows that there has been no proper coordination between the State Government, Ministry of Home Affairs and Planning Commission at the planning stage. The Committee are surprised that the State Government have fixed the target of bringing 50 per cent of tribal population above poverty line on a false assumption of a much larger Special Central Assistance and are now contemplating to scale down the target."

How has this been done ? How on a false assumption they have made, the programme, they have prepared it and the fund they have earmarked to be spent ? Further in other place it has been said,

"The Committee are surprised that the State Government of Orissa are not aware of the allocation of Rs. 6.5 crores available in the Plan Provision of the Ministry of Shipping and Transport for the development of roads in tribals areas under the Central Sector Roads Programme for 1980-85. The Committee emphasise that the State Government should immediately submit their proposals for road development in tribal areas and get the requisite funds."

In this connection, I do not blame any State Government here but they must be—whosoever it is, whether it is the Centre or the State—answerable and they must be held responsible. And, responsibility must be fixed, so that they do not waste time whenever we ask for information or when we ask why the implementation of their programme is not done in a proper manner. They must be answerable to Parliament or to the State Legislature. Whoever deals with this human problem, he should be held responsible for not implementing them. With these words I thank the hon. Member for bringing this problem to the notice of the country as well as this House.

MR. CHAIRMAN : Shri Ram Vilas Paswan.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपके पास कोई ऐसी मशीनरी या सिस्टम नहीं है जिससे कि आप अनएम्पलाएमेंट के मामले में किसी प्वाइंट पर पहुंच सकें। इसीलिए यह बेरोजगारी का मामला हमारे सामने बना हुआ है।

मैं शुरू से कहता आया हूं कि आप बेरोजगारों के आंकड़े रोजगार कार्यालयों से इकट्ठे करते हैं। मेरे जितने भी साथी हैं जो यहां बैठे हैं, या और भी जो पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं वे सब जानते हैं कि गांवों के दस परसेंट लोग भी रोजगार कार्यालयों में अपने नाम रजिस्टर नहीं करा पाते। हमारे पास अक्सर लोग नौकरी के लिए आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या रोजगार कार्यालय में नाम लिखाया है तो वे उत्तर देते हैं कि अभी तो नहीं लिख पाये हैं। आप हमेशा रोजगार कार्यालयों से डेटा कलेक्ट कर के हमको देते हैं। आपकी बेरोजगारों के बारे में योजना रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों पर ही बेस करती है लेकिन हकीकत यह है कि गांव के लोग उनमें नाम ही नहीं लिखते। गांव का यदि कोई आदमी शहर से संबंध रखता है तो वह रोजगार कार्यालय में अपना नाम लिखा लेता हो।

[श्री राम विलास पासवान]

मैं अपनी बात आपको बताता हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हम लोगों को गांव से शहर आना कठिन होता था। यह एक समस्या थी। इससे ही आप अनुमान लगाइये कि क्या कोई गांव का आदमी रोजगार कार्यालयों में अपना नाम लिखाने के लिए शहर आयेगा और फिर प्रत्येक तीन महीने के बाद उस नाम को रिन्यू कराना होता है। जिसकी जेब में दस रुपया होगा वही ऐसा कर सकेगा।

सब से पहली चीज तो यह है कि दो किस्म की बेरोजगारी है। एक अर्द्ध-बेरोजगारी और दूसरी पूर्ण बेरोजगारी। गांव में अधिकतर अर्द्ध-बेरोजगार लोग वे होते हैं जो कि भूमिहीन हैं। उन भूमिहीन मजदूरों को साल में मुश्किल से ढाई महीने काम मिल पाता है। जब काम मिलता है जब धान की, मकई की या गेहूं की फसल होती है। साल में दो बार, ढाई महीने के लिए या ज्यादा से ज्यादा तीन महीने के लिए काम मिल पाता है। फिर आपने मिनिमम वेज लागू कर दिया है। क्या कोई आदमी मिनिमम वेज लागू करवा सकता है? जिस आदमी को लेण्ड लार्ड के पास साल में मुश्किल से तीन महीने ही काम मिल पाता है, क्या वह लेण्ड लार्ड से यह कह सकेगा कि हमें मिनिमम वेज दो? वह कभी नहीं कह सकेगा। अगर वह कहेगा तो लेण्ड लार्ड कहेगा कि अच्छा तीन महीने का हम से मिनिमम वेज ले लो, उसके बाद हम तुमसे काम नहीं लेंगे। ऐसे अर्द्ध-बेरोजगार लोगों का आपके आंकड़ों में जिक्र नहीं आता है।

आप बेरोजगारों के आंकड़े इकट्ठे करने के लिए एक बार सारे देश में सर्वेक्षण कराइये। आप इन आंकड़ों को फिर अपने बीस सूत्री कार्यक्रम या अन्य किसी भी कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए पहले आप एक सूत्री कार्यक्रम बनाइये और बेरोजगार लोगों के सही आंकड़े इकट्ठे कीजिए।

आपने प्रथम योजना में कहा था कि 53 लाख बेरोजगार हैं, योजना में कहा था कि 71 लाख लोग बेरोजगार हैं, तृतीय में कहा था कि 126 लाख लोग बेरोजगार हैं। अभी 28 फरवरी, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 498 के उत्तर में आपने कहा है कि 1980 में 162 लाख बेरोजगार थे और 1981 में 178 लाख हो गये थे। 1982-83 में 197.53 लाख, 1983-84 में 219.53 लाख। इसी तरीके से आप देखिए एक प्रश्न के जवाब में 27.2.84 को शिक्षित बेरोजगारों के आंकड़े दिए गये हैं। शिक्षित बेरोजगार मेट्रिकुलेट 61.62 लाख, Persons who pass Higher Secondary 26.9 lakhs, graduates including post-graduates 19.42 lakhs, engineering graduates 241, skilled and unskilled 8.51 lakhs and so on.

ये है 1982-83 तक की जानकारी। इस तरह से बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। कभी-कभी यह देखकर आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है। नारायण दत्त तिवारी जी उस दिन अनाउंस करने आए, लगा जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए नई योजना बनाई गई है जिस के तहत 2.50 लाख बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार दिया जाएगा। आपके आंकड़ों के अनुसार 1985 तक बेरोजगारों की संख्या 3.5 करोड़ हो जाएगी। इस हिसाब से 1 करोड़ आदमियों को रोजगार देने के लिए 40 साल लगेंगे, दो करोड़ के लिए 80 साल और ढाई करोड़ के लिए 100 साल लगेंगे।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लोर) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। सभापति महोदय, इस सारी बात को बताने का क्या लाभ है। इन को चाहिए कि ये कुछ इस समस्या का हल बताएं कि क्या हल हो सकता है।

श्री राम विलास पासवान : तो सरकार की योजना के मुताबिक आज के बेरोजगार को 100 साल तक जिंदा रहना होगा और 100 साल तक जवान भी रहना होगा। कम से कम सरकार की कोई ऐसी योजना तो होनी चाहिए जिससे जो बेरोजगारी है वह और आगे न बढ़े। उस दिन चव्हाण साहब को बुरा लगा होगा। हम भी आवेश में आ गये थे। चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार, जवाब देही आपकी है। जब जानकारी दी गई है कि 1980-81 में 20.48 लाख टन अनाज दिया गया और खर्च हुआ 13 लाख टन। 1982-83 में 4.86 लाख टन अनाज दिया गया और खर्चा हुआ 1 लाख टन। 1980-81 में 127 करोड़ में से 36 करोड़ रु० खर्च किए गए और 1982-83 में 541 करोड़ में से 246 करोड़ रु० खर्च किये गए। जिस देश में इतनी बेरोजगारी हो वहां इस तरह की बात को कौन सहन करेगा। लक्ष्य आपने पूरा बता दिया। इधर उधर एडजस्टमेंट करके लक्ष्य आपने पूरा बता दिया। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बचपन में जब हम लोगों को कोई सवाल नहीं आता थी तो उसका उत्तर देखकर हम लोग सोचते थे कि किसी न किसी तरह से इसका उत्तर तो मिला ही दिया जाय। यही हाल आज यह सरकार कर रही है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि कम से कम सीलिंग बांध दीजिए कि एक परिवार में एक आदमी को एक रोजगार मिलेगा। यदि कोई सरकारी नौकरी में है तो वह नौकरी रखे या जमीन रखे। जो जमीन को बोए, वह ही उसका मालिक है। रूरल एरियाज में भी ऐसे लोग हैं जो बड़े-बड़े पदों पर हैं। अगर कोई जज है तो वह जज ही रहे, उसको जमीन न दी जाये। इस चीज को आप अलाऊ न कीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री कमल नाथ झा (सहरसा) : आपके कहने का मतलब है कि एक आदमी और एक पेशा।

श्री राम विलास पासवान : हां, मैं वही कह रहा हूं। जो काटेज इंडस्ट्री का मामला है, वह उसी स्तर पर रहना चाहिए। इस बात की पुरमिशन नहीं होनी चाहिए कि धीरे-धीरे उसको खत्म किया जाए। यदि खत्म करना है तो डिस्ट्रीक्ट लेवल पर बड़ा यूनिट करना पड़ेगा। "फूड फ़ार वर्क" प्रोग्राम में बहुत ज्यादा बगलिंग होती है। इसको इंकार नहीं किया जा सकता। जब लोगों को यह मालूम हो जाता था कि चार किलो मजदूरी मिलने वाली है और वह उसको न मिले तो वह कहता था कि यह ठेकेदार हमको तीन किलो मजदूरी देता है। पैसे को हड़पना आसान है लेकिन सामान को हड़पना कठिन है। उसके बदले में मिनिमम वेजेज देनी पड़ती थी जो कि आज नहीं दी जा रही है। मैं चाहता हूं कि यह प्रोग्राम ठीक तरह से चलाया जाए। बेरोजगारों को रोजगार का अधिकार दिया जाय। यह, दुनिया के तमाम समाजवादी मुल्कों में है। इसके लिए संसद में बहुत से बिल और रेजोल्युशन आए। आप कम से कम अन-एम्पलायमेंट अलाऊंस तो दीजिए। अगर, नहीं दे सकते हैं, तो सभापति जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपना इन्फ्लुयेंस सरकार पर लागू कीजिए। नौकरी के लिए जो आपने उम्र की सीमा

[श्री राम विलास पासवान]

बांध दी है कि 25 और तीस साल तक ही नौकरी मिल सकती है, उसको खत्म कीजिए। पचास साल की उम्र तक नौकरी मिलनी चाहिए, भले ही वह सात या आठ साल तक नौकरी में रहे। इसलिए, इस उम्र के व्यक्ति को भी नौकरी मिलनी चाहिये। आजकल जो क्राइम हो रहे हैं, वह सब अन-एम्पलायमेंट की वजह से ही हो रहे हैं। जितने भी क्रिमिनल्स हैं, वे सब यूथ ही होते हैं। उनकी उम्र बीस से पैंतीस साल तक हो होती है। जब पेट में आग लगती है तो किसी चीज की पूजा नहीं होती। यह भयावह समस्या है जो मुंह खोलकर सामने खड़ी है। प्लानिंग मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को चाहिये कि वे कोई ठोस प्रोग्राम चाकआउट करें जिससे बेकारों की समस्या पर काबू पाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN : The House must appreciate that this is a vast subject undoubtedly and it is very important also but once the House fixes the time, then we are bound by that time. This also has to be appreciated in a parallel manner. So, what I wish to request once again is that the speakers may just make points. There are three or four more speakers so we extend the time a little more, and I will request the Minister to very kindly agree. so that we come back to the old idea of extending the time by one hour... (*Interruptions*). Please don't interrupt. Let me finish. So, you very kindly extend the time on my recommendation now up to six o'clock so that everybody would be satisfied. My second appeal to you, the spokesmen—because I am also of the same category as you are—is that the subject is indeed very vast, one can speak on all the facets of it for hours, there is no doubt about that. It is a question of unemployment, labour's proper positioning and so on and so forth. So, each hon. Member should take only a few minutes. Somebody mentioned five minutes. Instead of that, you can take six or seven minutes. But, when I give the bell, try to finish it off It is not necessary that every hon. Member should give the same points time and again.

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : Considering the importance of this subject, from our side we have no objection to the extension of time. If it is necessary to give it adequate time, it can be continued even till the next day.

MR. CHAIRMAN : If the House is so keen, it can be done.

SOME HON. MEMBERS : Yes.

MR. CHAIRMAN : On your recommendation, as on exceptional case, it is done because I want to satisfy everybody.

*DR. V KULANDAIVELU (Chidambaram) : Hon. Mr. Chairman, Sir, my Hon friend Shri T.S Negi has through this resolution focussed the attention of the House on the growing unemployment in the country. The Hon. Members who preceded me referred to this grave issue and painted graphic picture. As our Chairman pointed out, this is a very big issue, having relevance to the economic and social development of the country. I welcome this Resolution and commend the efforts of Shri T.S. Negi for highlighting the problem on the floor of this House. Our Chairman has asked us to make our suggestions succinctly but even for that we require some time I will abide by his directive and restrict myself to a few concrete suggestions.

My Hon. friend, Shri Ram Vilas Paswan presented before the House all the statistics of unemployed in the country.

*Original speech was delivered in Tamil.

He also informed the House as to how the Government have not been able to tackle this problem so far. This problem has caused national concern. He said that 2.5 crores are unemployed in the country. I would say that the number of unemployed would be more than 2.5 crores, if you take into account the number of people who are partially employed, who are getting some jobs on occasions and who enjoy only seasonal job opportunities. I need not say that 80% of our people live in rural areas; depending on agriculture, which itself is a gamble in monsoon. Mosr of them are engaged on daily wages. Even here they are not assured of minimum wages. They have no hope of getting permanent jobs. If we include them, then the number of unemployed would be several crores in the country.

While this is the rural scene, what is obtaining in urban industrialised centres ? Here the contract labour system has proved to be the bane of our society. The private sector undertakings as also the public sector undertakings succumb to the pressure of these contractors. The workers are taken as casual labour for a week, then retrenched and after a week they are again employed. Thus the benefits of regular employment are denied to these workers.

Coming now to Employment Exchanges, I am afraid that they have become centres of corrruption in the country. All malpractices are resorted to in these places where lakhs and lakhs of youngsters have registered themselves No doubt some concessions have been given for scheduled caste and scheduled tribe candidates in the upper age limit. Upto 29 years there is relaxation for them. There is some chance for them till then. But here also they have to grease the palm of those working in Employment Exchanges. Where will these poor people go for doing this ? Then the employees in Employment Exchanges record on the file that so and so is unfit for the prescribed job etc. and the job is denied to those unable to pay money to them. They are kept in animated susensed till they reach the age of 29 years and then they are written off from the rolls. I can tell this House that several lakhs of scheduled caste and scheduled tribe unmployed youngsters aged 33 years are wandering from pillar to post. Even a qualified graduate becomes a victim of the avarice of the employees in Employment Exchanges. I have to make this charge that the Hon. Minister of Labour not taken effective steps to root out corruption in the Employment Exchanges.

In my parliamentary constituency we have the giant Neiveli Lignite Corporation. It is not that I am trying to highlight the problems of my constituency. I am saying by way of illustration. We have the lignite mines, thermal station, bricketting unit, urea plant, clay clay washing unit etc. here. In all these places even for maintenance works, contract labour is employed. Some two years ago, when my friend, Shri M.M. Lawrence brought before this House a Resolution to abolish the contract labour system, I referred to this problem. The contractor gets Rs. 20 to Rs. 50 per head for a particular job from the management. He passes on Rs. 4 or Rs. 5 or at the maximum Rs. 10 to the worker. The rest of the money is appropriated by him The ruling party dignitaries are also in league with the contractors and even the ruling party Ministers seem to encourage the labour contractors. The labourers are being emploited, The contractors do not employ destitutes or old men. They employ healthy young men, suck their blood and throw them out as physical wrecks, unfit for any other work. In the Food Corporation of India units, in the BHEL unit in Tiruchirappalli, for scavanging, for routine maintenance works, the contract labour system is being followed. I had written to the Minister concerned and I had also written to the Prime Minister emphasising the need for abolishing the contract labour system. Unfortunately, this is being perpetuated probably for pecuniary benefits to the higher-ups in such industrial units. I demand with all the force at my command that contract labour system should be abolished from the country Before I conclude, I would refer to the misuse of

[Dr. V. Kulandaivelu]

IRDP, NREP funds by AIADMK Government in Tamil Nadu. The people are being cheated by the State Government. In magazines like inlooker and other English papers many articles have been written about the mass deception being indulged in by the State Government. In the interest of tackling the unemployment situation in the country, the Central Government should ensure proper use of IRDP, NREP, Rural Employment Guarantee Scheme funds by the States. The contract labour system must be eliminated for ensuring employment opportunities in the country. With these words I conclude my speech, thanking you for the opportunity given to say these few words.

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति महोदय, यह सवाल केवल सिद्धांत का नहीं रह गया है कि पूंजीवादी सिस्टम में, चाहे वह अमरीका हो, जापान, जर्मनी, इटली फ्रांस या हिन्दुस्तान हो, बड़े-बड़े दावों के बावजूद बेकारी दूर नहीं होने वाली है। अब यह तथ्य पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि बेकारी की समस्या इस हुकूमत से दूर नहीं होने वाली है। बेकारी की समस्या इस हुकूमत से दूर होने वाली नही है। उस के लिए बुनियादी जो चेंज लाना पड़ेगा उन बातों को मैं छोड़ रहा हूं। उन बातों को भी छोड़ रहा हूं कि और क्या-क्या साल्यूशन बताए गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारा जिला है, प्लानिंग मिनिस्टर साहब जानते हैं, वह पिछड़ा हुआ जिला है। चम्पारन और पूर्वी चम्पारन बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। पूर्वी चम्पारन और चम्पारन में राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधी जी ने बड़ी भूमिका अदा की थी। लेकिन पूर्वी चम्पारन में जो अंग्रेजों के समय में कारखाने खुले, चीनी मिलें खुलीं, उस के बाद से आज तक कोई नये कारखाने नहीं खुले हैं। मैं कहता हूं कि बुनियादी रूप से बेकारी इस से दूर नहीं हो सकती। लेकिन जो हो सकता है उस की बात कहता हूं। मैं चाहूंगा कि चीनी मिलों के अलावा चम्पारन में दूसरे और कारखाने खोलने के लिए सोचिये। मैं लगातार पन्द्रह सालों से आप से कह रहा हूं लेकिन इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

ग्रामीण इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना की बात तीन सालों से पड़ी हुई है लेकिन इंडस्ट्रियल एस्टेट के विकास के लिए भूमि लेने और उस की स्थापना करने का कोई काम नहीं हो रहा है। ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि उस इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना होनी चाहिए और उस के कार्य में प्रगति लानी चाहिए ताकि वहां के लोगों को छोटे मोटे काम खोलने की सुविधा मिल सके।

मेरे यहां पुरानी इंडस्ट्री जो है उस का भी नवीकरण और आधुनीकरण होना चाहिए। इस बात की भी समस्या है। इस से भी कुछ काम लोगों को मिल सकता है।

रामा कास्ट आयरन मोतीहारी में एक कारखाना है। उसने सरकारी बैंकों से करोड़ों रुपये कर्जा लिया है और उस के बावजूद चूंकि वह बिरला की कंपनी है और नोपानी की कम्पनी है चार सालों से वह बंद है, हजारों मजदूर बेकार पड़े हैं। मैंने प्लानिंग मिनिस्टर को पत्र लिखा, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को पत्र लिखा, इंडस्ट्रियल सलाहकार समिति का दो साल से मेम्बर हूं, सब जगह कहने के बावजूद भी चूंकि नोपानी के डर से आप थर-थर कांपते हैं इसलिए उसको चलाने के लिए कोई काम नहीं किया है।

हमारे यहां आदापुर एक इलाका है जहां गन्ने की पैदावार बहुत अधिक होती है। चम्पारन जिले का औद्योगिक विकास हो, लोगों को काम मिले इस के लिए आदापुर में चीनी मिल का खुलना बहुत आवश्यक है। लेकिन आज तक उस के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह चाहे प्राइवेट मिल मालिक खोलें या कोई खोले, लेकिन खोलना तो चाहिए लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

ऐसे ही एक इलाका है बाड़ा चकिया, वहां जूट बहुत होता है। जूट का वह एक सेंटर है। हजारों लोगों की मांग है कि बाड़ा चकिया में एक जूट मिल खोल दी जाय तो उस से सैकड़ों लोगों को काम मिल सकता है। लेकिन इस विषय में भी कोई प्रगति नहीं हुई है।

हमारे यहां जो चीनी मिलें हैं उन का बागास फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, किसी काम में वह नहीं आता। उस बागास के आधार पर वहां कारखाना खोला जा सकता है, पल्प इंडस्ट्री खोली जा सकती है। इन संभावनाओं को सरकार को खोजना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।

ऐसे ही चीनी मिलों से मोलेसिस निकलता है। उस की बेसिस पर स्पिरिट का कारखाना चलाया जा सकता है। यह चम्पारन जिले की मांग है, हम ने इस के लिए बार-बार कहा है लोग कहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के आप हैं आप लोग कहते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग भी इस पर जोर देते रहे हैं। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

हमारे यहां खेती-प्रधान इलाका है, खेती पर आधारित उद्योग वहां खोले जाने चाहिये। लेकिन यह काम भी नहीं हो रहा है। हमारे इलाके में लीची और आम बहुत होता है। लीची और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खुल सकती है, आम की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खुल सकती है, फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहां बहुत अच्छी चल सकती है। हम लोग मांग करते हैं कि यह इंडस्ट्री वहां खोली जानी चाहिए।

चम्पारन जिले में बड़ी-बड़ी लेक्स हैं। उन लेक्स में मछली पाली जा सकती हैं। मत्स्य पालन के द्वारा हजारों मछुओं का जीवन-यापन हो सकता है लेकिन वहां पर ठेकेदारों को ठेके दे दिये जाते हैं और उन लेक्स का विकास भी नहीं हो पाता है। चम्पारन जिले में मछली उद्योग एक अच्छा उद्योग बन सकता है और मछली के द्वारा प्रोटीन की भी प्राप्ति हो सकती है।

सभापति जी, बीस सूत्री कार्यक्रम में तीसरा सूत्र भूमि सुधार के संबंध में है लेकिन अभी तक वहां पर इस संबंध में कोई कार्य नहीं किया गया है। बटाईदार इस संबंध में लड़ रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ जजमेंट दिये जा रहे हैं। आपने भूमि सुधारों का एलान किया है लेकिन उस संबंध में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। हमारे यहां मेन गण्डक कैनाल बन चुकी है लेकिन ड्रेनेज का काम नहीं किया जा रहा है जिसके द्वारा लाखों लोगों को काम मिल सकता है। ड्रेनेज का काम शुरू करने के लिए बिहार सरकार के पास पैसा ही नहीं है। अफसरों को तो हर महीने तनख्वाह मिलती है लेकिन बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। इसी प्रकार की अन्य योजनायें भी यदि लागू की जायें तो लोगों को काम उपलब्ध हो सकता है। एम्पलायमेंट ओरि-

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

एन्टेड स्कीम्स के अन्तर्गत जो सड़कें बनाई गई उसकी हालत बहुत खराब है।

इसी प्रकार से नदियों पर तटबंध बनाने का सवाल भी है। गण्डक, बागमती जैसी नदियों पर तटबंध न बनने से हजारों एकड़ जमीन हर साल बाढ़ से कट जाती है। तटबंध की स्कीमें तो हैं लेकिन उनके लिए सरकार के पास पैसा नहीं। यदि तटबंध बनाने का काम भी वहां पर चालू कर दिया जाये तो तमाम लोगों को रोजगार मिल सकता है। वहां पर चमड़ा उद्योग का काम भी चलाया जा सकता है। कुछ छोटे-छोटे कारखाने खोले जा रहे हैं लेकिन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की जो हालत सारे देश में है वही चम्पारन जिले में भी है। बाजार, पूंजी और रॉ-मैटीरियल के अभाव में कोई प्रगति नहीं हो रही है। हथकरघा उद्योग जो है उसमें जुलाहों को जो सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। ऐसी दशा में हथकर्घा उद्योग भी नहीं पनप पा रहा है।

जहां तक खेत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न है, राम विलास जी ने सही कहा है कि चूंकि किसानों को लाभकर मूल्य नहीं मिल रहे हैं और उनके बकाए का भुगतान नहीं हो रहा है इसलिए खेत मजदूरों की समस्या को हल करने में भी कोई सहायता नहीं मिल रही है। इसलिये आवश्यक है कि सरकार भूमि सुधारों को लागू करे, किसानों को लाभकारी मूल्य दे और उनके बकाए का भुगतान करवाये ताकि खेत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की जो सम ा है उसका भी हल निकल सके।

बीस सूत्री कार्मक्रम के नाम पर आपने जो कार्यक्रम चलाये हैं वह लूट के कार्यक्रम हैं। चाहे एन० आर० ई० पी० हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो सभी जगह यही स्थिति दिखाई दे रही है। आप अनएम्पलायड ग्रेजुएट्स जो 25 हजार रुपया देते हैं उसमें से उनको 5 हजार तो घूस में ही देने पड़ जाते हैं। आप बताइये उसके बाद वह कौन सा कारखाना लगा सकता है। मैं तो कहूंगा कि सही मायनों में बेकारी दूर करने के लिये आपको फंडामेन्टल चेंज लाना पड़ेगा जोकि आप कर नहीं सकते हैं। वह तो दूसरे लोग ही आकर करेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय सभापति जी, आज बेरोजगारी का विषय बहुत ही गंभीर विषय है। इस सदन में इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है और बहुत से आंकड़े भी दिए जा चुके हैं। समय की कमी की वजह से मैं आपसे वचनबद्ध हूं कि मैं अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करूंगा।

मान्यवर, जैसा कि पूर्ववक्ताओं ने कहा, बेरोजगारी की समस्यायें शहरों में तो हैं हीं, लेकिन गांवों में बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि हमने अखबारों में देखा है बेरोजगारी की वजह हमारी मातायें और बहनें अस्मत को भी बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं को सुनकर बड़ा ही ताज्जुब होता है और शर्म आती है कि लोग अपनी इज्जत और मर्यादा को बेचकर भी रोजगार प्राप्त करने में आज असफल हैं।

मैं चाहूंगा कि हमारे श्रम मंत्री जी बहुत ही विवेकशील हैं उनको अनुभव भी है, क्योंकि वे इसको भोग भी चुके हैं। मैं चाहूंगा क्योंकि आप शासन में हैं, यदि आप

कुछ कर सकते हैं, तो करें। यह निश्चय ही देश के लिए बहुत बड़ा महान कार्य होगा।

बेरोजगारी के संबंध में बहुत से आंकड़े दिये गये हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 33 लाख बेकार थे, जिसमें 90 लाख और बढ़ कर 123 लाख हो गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 53 लाख थे, 118 लाख और बढ़ कर 171 लाख हो गए। इसी प्रकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 171 लाख थे 280 लाख बढ़कर 451 लाख हो गए। इस प्रकार बेरोजगारी की रफ्तार बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। यदि इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार कदम उठाए और 5-10 प्रतिशत ही कम करें तो मैं समझता हूं कि सरकार ने इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

मुझे बीस सूत्री कार्यक्रम के सिद्धांत के बारे में कोई शिकायत नहीं है। आपने जरूर इस कार्यक्रम के मुताबिक गांवों में रोजगार देने की योजना बनाई है। जनता पार्टी के जमाने में फूड फार वर्क की योजना थी, इस समय आपने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस को चलाया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे इस योजना से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जनता के अन्दर इस कार्यक्रम के प्रति रोष है। वह बहुत परेशान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत हरिजन समाजकल्याण मंत्रालय ने हरिजनों और दूसरे लोगों को सब्सिडी देने की एक योजना बनाई है। किसी को रोजगार करने के लिए दस हजार रु० यदि दिए जाते हैं, तो उसमें पांच हजार रुपए बैंक के मैनेजर और दूसरे लोग मिल कर खा जाते हैं। इस प्रकार की बहुत सी नजीरें मेरे पास हैं, जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको अपने बनारस जिले के बारे में कहना चाहता हूं। मैं पहले कई बार इस सदन में वाराणसी, मिर्जापुर और जौनपुर तीनों जिलों के आंकड़े दे चुका हूं। यदि वहां किसी को रिक्शा खरीदने के लिए दो हजार रु० दिए जाते हैं, उसमें से दो रुपया तो बाबू और 300 रुपया वहां का ग्राम सेवक खा जाता है। इसी प्रकार यदि वहां पर भैंस खरीदी जाती है, तो दो हजार रु० की भैंस के स्थान पर तीन हजार रु० वसूल किये जाते हैं। कहा जाता है कि यह भैंस हमने पंजाब से मंगाई है। इस प्रकार उसके नाम तीन हजार रुपये लिख दिये जाते हैं, जिसको वह चुका पाने में असमर्थ हो जाता है। मैं चाहूंगा कि इन समस्याओं के ऊपर हमारे श्रम मंत्री और योजना मंत्री, जो अच्छी तरह से जानते हैं, ध्यान दें और इन चीजों को खत्म करें।

मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा मेरे पूर्व साथी ने बतलाया था, इस देश में किसान 6 महीने बेकार रहता है। महाराष्ट्र में 180 दिन, पंजाब में 150 दिन और उत्तर भारत में 200 दिन काम करता है यानी कुल मिलाकर 6 महीने काम करता है और 6 महीने बेकार रहता है। मैं चाहूंगा कि एग्रीकल्चर मंत्रालय इस ओर ध्यान दे और देश में सघन कृषि डवेलप करे। सघन खेती डवेलप करने से विभिन्न फसलों को उत्पादन में लाया जायगा, इस से मेरा विश्वास है बेरोजगारी जरूर कम होगी।

इस में सन्देह नहीं है कि हमारे देश में जमीन ज्यादा है—हमारा कर्त्तव्य है कि जमीन को उपजाऊ बनाया जाय, बंजर जमीनों को ठीक किया जाय तथा छोटे

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

उद्योगों को बढ़ाया जाय । इस के साथ-साथ जैसा मेरे एक साथी ने बतलाया था और मैं भी उस पर विशेष जोर दे कर कहना चाहता हूं—हर संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक बड़ा प्लान जरूर बनाया जाय । एक संसदीय क्षेत्र प्राय: 5 लाख से लेकर 7 लाख तक एक एडल्ट आबादी होती है और इस एडल्ट आबादी में, जैसा हम लोगों ने तखमीना लगाया है, 25 से 30 हजार लोग बेकार रहते हैं जो शहरों में जा कर छोटे मोटे काम करते है, रिक्शा चलाते हैं और इन से क्राइम भी बढ़ता है । मैं चाहता हूं कि क्राइम को कम करने के लिये और गांव में ही रोजगार देने के लिए एक संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक बड़ा उद्योग लगाना चाहिए जिस में चार-पांच हजार आदमी काम कर सके ।

सभापति महोदय, इस प्रस्ताव को इस सदन में ला कर हमारे नेगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है जिस से बेरोजगारी की ओर सदन का ध्यान खींचा जा सका है तथा इसके अच्छे निष्कर्ष निकले हैं । बहुत से लोगों ने भिन्न-भिन्न आंकड़े दिये हैं जिन से पर्याप्त जानकारी हासिल हुई है । इन शब्दों के साथ मैं नेगी जी को इस प्रस्ताव को यहां लाने के लिये बधाई देता हूं ।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चेअरमैन साहब, मैं पंजाब में 8-10 साल लेबर मिनिस्टर रहा हूं । जब मैं किसी कारखाने को देखा जाता था और देखता था कि वहां मजदूरों को मुनासिब मजदूरी नहीं मिलती है, लेबर तंग होती थी, तो मैं वहां लेबर को कह दिया करता था कि तुम हड़ताल कर दो और वे हड़ताल कर देते थे और उस के बाद उन की मजदूरी का पैसा बढ़ा दिया जाता था । मैं लेबर मिनिस्टर से यह कहूंगा कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिये ।

महात्मा गांधी पढ़े-लिखे लोगों से कहा करते थे कि तुम एक महीने लेबर का काम करो जिससे तुम को भी पता लगे कि लेबर क्या चीज है । आज जो पढ़े-लिखे हैं वे कोई काम नहीं करना चाहते हैं, सब को नौकरी चाहिये । जो नौकरी कर रहे हैं वे अपनी ड्यूटी ठीक तरह से अदा नहीं करते हैं, यह लेबर महकमे की ही बात नहीं है, आप किसी भी महकमे को ले लो, कोई भी अपनी ड्यूटी सही तरीके से अदा नहीं करता है, भट्टा ही बैठा दिया है । यह पासवान क्या करता है —सिर्फ नुकताचीनी करता है, इसलिये इस को भी कोई काम मिलना चाहिए जिससे वह कोई अच्छा काम करे ।

ये कहते हैं कि यू० पी० में पानी नहीं है— किस का कुसूर है ? .

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप पंजाब की बात करो । वहां इतना पानी है कि अट नहीं रहा है ।

श्री सुन्दर सिंह : हमारे लोग वहां जा कर फार्म बना लेते हैं, खूब रोटी कमाते है, तुम क्यों नहीं कमाते हो ? अगर कहीं पानी नहीं है तो वहां का एम०एल०ए० क्या करता है, शोर क्यों नहीं मचाता है कि वहां पानी चाहिये, नहर चाहिए। सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहां आकर कहेंगे तो उससे क्या होगा ? इस में लेबर मिनिस्टर क्या कर सकता है ? यह महात्मा गांधी का मुल्क है । महात्मा गांधी ने जिस ढंग से लड़ाई की थी, उस ढंग से लड़ाई करनी चाहिये । वह कभी वेला नहीं बैठा । मैं बाहर गया था

और वहां मैंने देखा कि कोई आदमी बेला नहीं बैठा है और सब काम में लगे हुए हैं और यहां पर हम देखते हैं कि लोग बेकार घूमते फिरते हैं। मेरे पास आ कर ठहरते हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। उनको लेना-देना नहीं है और वे निकम्मे बने रहते हैं। बगैर काम किये उनको रोटी मिल जाती है। आदमी का फर्ज होना चाहिये कि वह कमा कर खाए।

एक दिक्कत और है। सब लोग चाहते हैं कि उसे नौकरी मिल जाए। नौकरी क्या चीज होती है। जो आदमी पढ़ा-लिखा है, उस को काम करना चाहिए चाहे वह कोई भी काम हो और यह सोसायटी का कसूर है अगर वह उसे काम न दे। जो भी काम मिले, वह उसे करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि अब खेती-बाड़ी में भी मशीनें काम आने लगी हैं और मजदूर बेकार बैठे रहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मशीनें बन्द करो, फिर काम चलेगा क्योंकि इस से आप डेड मशीनों की मदद करते हैं लेकिन जो आदमी हैं, उन की मदद नहीं करते हैं।

> "Dead machinery must not be pitted against the millions of living machines represented by the villagers scattered in the seven hundred thousand villagers of India.
>
> Machinery to be well used has to help and ease human effort. The present use of machinery tends more and more to concentrate wealth in the hands of a few in total disregard of millions of men and women whose bread is snatched by it out of their mouths."
>
> —Mahatma Gandhi

मशीनें जो इस्तेमाल करते हैं, उससे आदमी बेकार हो जाते हैं। इस तरह से आप उन की मदद नहीं करते हैं। लोग काम नहीं करते हैं और जहां लोगों के पास जमीनें हैं, वहां पर आदमियों को काम मिलना चाहिये। मैंने देखा है कि यू० पी० के लोग चंडीगढ़ में रिक्शा ड्राइवर बने हुए हैं। वे अपने यहां जमीनों पर काम नहीं करते हैं। आप यह देखिये कि पंजाब का आदमी काम कर रहा है और इस से प्रोडक्शन बढ़ रही है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि लोग काम नहीं करते हैं और दिन-रात बच्चे पैदा करते हैं, जिससे अनएम्पलायमेंट की प्राब्लम और ज्यादा बढ़ गई है। जब काम नहीं मिलता है, तो जो लोग अनएम्पलायड हैं, वे लोगों को मार रहे हैं। अगर उन को काम दे दिया जाये, तो ऐसी बात न हो। इस बारे में हमारे जो मेम्बर साहबान हैं, उनका काम भी यह है कि ऐसे लोगों को काम दिलाने में मदद करें। आज उन को रोटी नहीं मिलती है, इसलिए वे ऐसा करते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर इंडस्ट्री लगा दी जाए। मेरा कहना यह है कि हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चरल मुल्क है और यहां पर अगर किसी के पास 5 एकड़ जमीन है, तो उस में 10 आदमी गुजारा कर सकते हैं। यह इंडस्ट्रियल मुल्क नहीं है, यह एग्रीकल्चरल मुल्क है। एग्रीकल्चरल में आपने मदद नहीं की और मेरा कहना तो यह है कि अगर लैंड रिफार्मस हो जाते, तो एम्पलायमेंट लोगों को मिल सकता था और वह जो अनएम्पलायमेंट की प्राब्लम है, यह सोल्व हो सकती थी। कुछ लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री लगा देंगे या कारखाने लगा देंगे, तो लोगों को नौकरी मिल जाएगी। मैं यह भी समझता हूं कि यह स्टेट का काम है कि

[श्री सुन्दर सिंह]

लोगों को काम दे और यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। स्टेट में एम० एल० एज जो हैं, वे इनके लिए कुछ कर सकते हैं। यहां कहने से क्या हो सकता है। हिन्दुस्तान एक एग्रीकल्चरल मुल्क है और यह इंडस्ट्रियल मुल्क नहीं है। अगर लैंड रिफार्म यहां हो जाएं, तो लोगों को भी काम मिल सकता है और बाहर से हमें अनाज भी नहीं मंगाना पड़ेगा। यह असली बात है और इस पर जोर नहीं देते हैं। बहुत से कांग्रेस के लोग भी ऐसे हैं, जो इस को नहीं करने देते और अपोजीशन वाले तो करने देते ही नहीं हैं।

अपोजिशन वालों के बारे में मैं जानता हूं कि इनके पास भी दो-दो, तीन-तीन सौ एकड़ जमीन है। ये उस जमीन के पास किसी को नजदीक नहीं आने देते। मर जायेंगे पर उस पर किसी को काम नहीं करने देंगे।

महात्मा गांधी ने लिखा है—

"I suggest we are all thieves in a way. If I take anythings, that is not for our immediate use and I keep it for anybody else."

— Mahatma Gandhi

मुझ को पता है कि मिनिस्टर कैसे काम करते हैं। उनके महकमे में सारी ब्यूरोक्रेसी काम करती है। अगर मिनिस्टर अपने महकमे को ठीक से देखें तो किसी की मजाल है कि वहां कोई काम न करे। उनके महकमों में जो सेक्रेटरी होते हैं वे काम करते हैं।

सभापति जी, जब मैं मिनिस्टर था, मजाल है कि कोई काम न करे। आज के मिनिस्टर ऐसे हैं कि उनके सेक्रेटरी काम करते हैं। जिसका महकमा हो, उस महकमे के मिनिस्टर को कुसूरवार होना चाहिए अगर उस महकमे में काम न हो।

अपोजिशन वाले अनएम्पलायमेंट की बहुत बात करते हैं और कहते हैं कि अनएम्पलायमेंट का भत्ता दे दो। इस से कहीं यह चीज दूर हो सकती है मैं कहता हूं कि आप लैंड रिफार्म्स करो और मिनिस्टर लोग अपने-अपने महकमे संभालें। अगर आप लैंड रिफार्म्स नहीं करेंगे तो उसका नतीजा अनएम्पलायमेंट होगा। लैंड रिफार्म्स न होने के कारण ही आज अनएम्पलायमेंट ज्यादा है। हरेक इलाके के एम० एल० ए० या एम० पी० का कुसूर है अगर वह अपने इलाके में इन चीजों को नहीं देखे, इससे उसके इलाके के लोगों को तकलीफ होती है। हरेक एम० एल० ए० और एम० पी० को अपने इलाके की तकलीफों को देखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। आप मुझे हमेशा उस वक्त समय देते हैं जब कोई सुनने वाला नहीं होता।

MR. CHAIRMAN : For the information of the House, the turn now is for Private Members' Bills And, further on at the next sitting, the Hon. Minister will intervene and then there will be a reply. That is in so far as this particular list of business is concerned.

Now, the House stands adjourned to meet again at 11 A.M. on 2nd April, 1984.

18.04 hrs.

The Lok Sabha then adjourned to meet again at 11 A.M. on Monday, the 2nd April, 1984/Chaitra 13, 1906 (Saka).

———

Akashdeep Printers, 20, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002.